संस्करण : भोपाल
वर्ष : 01
अंक : 222
पृष्ठ : 08
मूल्य : 1.00
बुधवार 11 अक्टूबर 2026

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

प्रातःकाल एक्सप्रेस

प्रातःकालीन संस्करण

सच से रूबरू



Website:www.pratahkalexpress.in | E-mail :pratahkalexpress@gmail.com | facebook.com/pratahkalexpressnews | https://twitter.com/ratahkalexpress1

सरकार बनी तो राशन में देंगे सरसों का तेल'

अखिलेश बोले-अयोध्या में महिलाओं से हुई अभद्रता की जांच करे आयोग



लखनऊ (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में भाजपा के कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के साथ हुई कथित मारपीट और अभद्रता को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने महिला आयोग से मामले का संज्ञान लेकर भाजपा के संबंधित नेताओं और आयोजकों के खिलाफ वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लोग नारी का सम्मान नहीं, अपमान करते हैं। अखिलेश यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कुछ महीनों बाद प्रदेश में पीडीए सरकार बनने पर राशन में सरसों का तेल दिया जाएगा। इससे शोषित, वंचित और गरीब लोगों को कथित तौर पर भाजपा के उत्पीड़न और अपमान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा से पीड़ित और अपमानित लोग इस बार उसका स्थायी सफाया कर देंगे। सपा अध्यक्ष ने लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले युवक की मां का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से सार्वजनिक रूप से उस दुखी मां का किया गया अपमान कोई महिला नहीं भूलेगी। अखिलेश ने इसे मातृशक्ति का अपमान बताते हुए कहा कि उसका श्राप खाली नहीं जाएगा।उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 के विधान परिषद चुनाव का हवाला देते हुए दावा किया कि भाजपा के जुमलों का असर जनता के बीच खत्म हो रहा है।

देशभर में दिवाली की रात आग से 23 मौतें

महाराष्ट्र में 13 की जान गई, महाराष्ट्र में एक ही परिवार के 6 की मौत



नई दिल्ली(एजेंसी)। दिवाली की रात देश के कई शहरों में पटाखों और अन्य कारणों से लगी आग में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल और कुछ लापता हैं। सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुईं, जहां तीन अलग-अलग घरों में आग लगने से 13 लोगों की जान चली गई। वहीं महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में एक मकान में रहने वाले परिवार के छह लोगों की मौत हो गई। मुंबई के लोखंडवाला में आग लगने की एक अन्य घटना में भी एक व्यक्ति की जान चली गई। इसके अलावा, राजस्थान के पाली में पटाखों की दुकान में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता हैं। हादसे में तीन दुकानें और कई दोपहिया वाहन जल गए। वहीं, दिल्ली के नरेला में रॉकेट पटाखा पेट में लगने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई।मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मकान में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं जिनमें से एक 2 महीने का था।वहीं, सिवनी जिले में सराफा व्यापारी के मकान में आग लगने से 6 लोगों की जान चली गई। इनमें एक 16 साल का किशोर भी शामिल हैउत्तर प्रदेश के बांदा में कबाड़ की दुकान में आग लगने से करीब 20-25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुणे में आग की 63 घटनाएं हुईं, इनमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।जम्मू के नेहरू मार्केट में आग से 12 से ज्यादा दुकानें जल गईं, जबकि नागपुर में टीवीएस शोरूम में आग लगने से कई दोपहिया वाहन जल गए।मुंबई के डोंगरी में झुग्गियों में आग मुंबई के डोंगरी इलाके में आग से कई दुकानें और झुग्गियां जल गईं, जबकि दादर के कामगार स्टेडियम में लगी आग पर दमकलकर्मियों ने 17 मिनट में काबू पा लिया। महाराष्ट्र के ठाणे में 17 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी। ठाणे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

इसके अलावा असम के जोनाई, पुणे के वडगांव शेरी, मुंबई के विद्याविहार, सिक्किम के गंगटोक में सरकारी आवास और गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में भी आग लगने की घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं के बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रहीं।

'दिल्ली के खिलाफ साजिश': मंत्री कपिल मिश्रा का बड़ा दावा

बोले-पंजाब में दिवाली की रात 1200 जगह जलाई पराली



नई दिल्ली(एजेंसी)। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने पंजाब के खेतों में पराली जलाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश बताया है। मिश्रा ने कहा कि उन्हें पंजाब के किसानों से खेतों में आग लगाए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। दिवाली के दिन 1200 स्थानों पर पराली जलाई गई।

मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि किसानों ने शिकायत की कि दिवाली मनाते समय उनके खेतों में रात में आग लगाई जा रही थी। आग लगाने वाले लोग तुरंत मौके से भाग जाते थे। शुरूआत में उन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने भारत सरकार के पराली जलाने के सैटेलाइट डेटा की जांच की। इस डेटा से साबित हुआ कि यह एक पूर्व नियोजित कदम था। पंजाब के खेतों में जानबूझकर आग लगाई गई थी। 5, 6 और 7 नवंबर के सैटेलाइट डेटा के अनुसार, 125 स्थानों पर पराली जलाई गई थी। लेकिन पिछली शाम के डेटा के अनुसार, दिवाली के दिन 1200 स्थानों पर पराली जलाई गई। यह संख्या में 10 गुना की वृद्धि थी। उन्होंने इस वृद्धि को बेहद गंभीर मामला बताया। सैटेलाइट डेटा से खुलासा कपिल मिश्रा ने कहा कि सैटेलाइट डेटा ने चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। पराली जलाने की 125 घटनाएं दर्ज की गई थीं। लेकिन दिवाली के दिन, यह आंकड़ा बढ़कर 1200 स्थानों तक पहुंच गया। ये बताता है कि दिवाली के मौके पर जानबूझकर आगजनी की गई। उन्होंने इस अचानक हुई वृद्धि पर सवाल उठाए।

सीएम योगी बोले: हर हाल में करनी है गाय की रक्षा

प्रदेश में 7700 गोशालाओं में 16 लाख निराश्रित गोवंश संरक्षित



गोरखपुर (एजेंसी)। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की गोशाला में विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गोवर्धन पूजा की। गोपूजन के बाद उन्होंने गायों और गोवंश को माला पहनाई, तिलक लगाया और अपने हाथों से गुड़-केला खिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री गायों को उनके नाम से पुकारते और दुलारते भी नजर आए। उन्होंने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर हाल में गाय की रक्षा करनी है। गोवंश की नस्ल सुधार की दिशा में भी प्रयास करने होंगे, ताकि पशुपालकों को समृद्ध बनाया जा सके। दिवाली के दिन रविवार से गोरखपुर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री ने सोमवार सुबह मंदिर परिसर स्थित गोशाला में पूजन किया। उन्होंने गोमाता का आशीर्वाद लेकर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में गोसंरक्षण और गोसंवर्धन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोमहत्ता को प्रतिष्ठित करने वाली परंपरा के निर्वहन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 7,700 से अधिक गोशालाओं के माध्यम से निराश्रित गोवंश के संरक्षण और संवर्धन का कार्यक्रम चला रही है। इन गोशालाओं में 16 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं। सरकार का प्रयास है कि गोवंश को सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान मिले। सीएम योगी ने बताया कि गोसंरक्षण और गोसंवर्धन के लिए सरकार तीन तरह की योजनाएं चला रही है। पहली योजना के तहत निराश्रित गोआश्रय स्थलों का संचालन सरकार करती है। दूसरी सहभागिता योजना है। इसके तहत किसान गोआश्रय स्थल से निराश्रित गाय लेकर उनका पालन-पोषण कर सकता है। सरकार इसके लिए प्रति गाय 1,500 रुपये प्रतिमाह देती है। एक किसान अधिकतम चार गाय रख सकता है। इस तरह उसे हर महीने छह हजार रुपये तक की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुपोषित परिवारों को भी दूध की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए गोआश्रय स्थल से एक-एक ब्याई हुई गाय दी जाती है। इसके पालन-पोषण के लिए परिवार को प्रति गाय 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। इन योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में किसानों और कुपोषित परिवारों ने लिया है। गाय सड़कों पर न हो, यही सरकार का ध्येय मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी व्यवस्था के तहत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में गोआश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन विभाग और शहरों में नगर विकास विभाग के माध्यम से कान्हा उपवन संचालित होते हैं।

बांग्लादेश: क्या दिसंबर में लौटेंगी शेख हसीना

नए पासपोर्ट के आवेदन से बढ़ी हलचल; वकील ने किया खुलासा



बांग्लादेश (एजेंसी)। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। वह करीब दो साल पहले विद्रोह के बाद सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारत में निर्वासन में रह रही हैं। पासपोर्ट के लिए यह आवेदन उनके बांग्लादेश लौटने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हसीना ने इसी महीने एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि वह हर हाल में दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी। बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। हालांकि, सरकार पहले उन सुझावों को खारिज कर चुकी है, जिनमें कहा गया था कि देश लौटने के लिए हसीना को नए पहचान दस्तावेजों की जरूरत है। एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के मुताबिक, हसीना के एक वकील ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी राजनयिक मिशन को ईमेल भेजकर शीर्ष राजनयिक से उन्हें पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। हसीना के सहयोगी अबू ओबैदा अरिन ने एपी से कहा, 'यह उनकी घर वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले शासन ने उनके दस्तावेज रद्द कर दिए थे। अब वह एक बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर अपने मौलिक अधिकार दोबारा हासिल करने और जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने की उम्मीद कर रही हैं।' उन्होंने कहा कि हसीना दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने के लिए दृढ़ हैं और वह निश्चित रूप से अपने देश वापस आएंगी। इस मामले पर बांग्लादेश सरकार की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने क्या कहा?

इस बीच, बांग्लादेश के विदेश मामलों के मंत्री हुमायूं कबीर ने बृहस्पतिवार को कहा था कि उनकी सरकार भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना को वापस लाना चाहती है।

श्रीनगर में 4 आतंकियों की तलाश लालचौक पर बैनर लगा



श्रीनगर (एजेंसी)। लाल चौक इलाके में रविवार सुबह चार वांटेड आतंकियों की जानकारी मांगने वाला बैनर लगाया गया है। यह बैनर प्रताप पार्क की दीवार पर टांगा गया है। इसमें आतंकियों के नाम और तस्वीरें हैं।बैनर में मोहम्मद लतीफ भट की तस्वीर भी शामिल है। वह इस साल जुलाई में अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल था।इसके अलावा बिलाल अहमद मीर, मोहम्मद उमर मीर और आबिद कयूम लोन का नाम भी है। ये तीनों बारामूला जिले के रहने वाले हैं। बैनर पर लिखा है, ह्लजो भी इन आतंकियों की आवाजाही या मौजूदगी के बारे में विश्वसनीय जानकारी दे सकता है, उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और अच्छा इनाम दिया जाएगा। इससे पहले अगस्त-सितंबर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने वांछित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) आतंकी लतीफ अहमद भट की गिरफ्तारी के लिए श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगाए हैं। एजेंसी ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने पर 15 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। लतीफ अहमद भट लश्कर-ए-तैयबा का एक शीर्ष कमांडर माना जा रहा है।

दिल्ली के नरेला में दर्दनाक हादसा: दिवाली पर रॉकेट बच्चे के पेट में घुसा, मासूम की मौत



नई दिल्ली(एजेंसी)। दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र में दिवाली वाले दिन एक अत्यंत दर्दनाक हादसा सामने आया। इस घटना में 10 साल के एक बच्चे की जान चली गई, जिससे पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जानकारी के अनुसार, बच्चा दिवाली की पूजा संपन्न होने के बाद पटाखे चला रहा था। वह रॉकेट भी चला रहा था, तभी एक रॉकेट आसमान में ऊपर जाने की बजाय सीधे उसके पेट में जा घुसा। रॉकेट के पेट में घुसने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद बच्चे के परिजन गहरे सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है। रविवार की रात लगभग 10:50 बजे अस्पताल से सूचना मिली कि बच्चे को मृत अवस्था में लाया गया था। उसकी मौत पटाखे से लगी चोटों (जलने) के कारण हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मृतक बच्चे की मां अंजलि कहती हैं, "मेरा बेटा पटाखे जला रहा था; बाकी सब भी ऐसा ही कर रहे थे।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर बस खाई में गिरी, 3 की मौत

मासूम बच्चों समेत 40 घायल; राजस्थान से बिहार जा रहे थे



लखनऊ (एजेंसी)। आगरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह यात्रियों से भरी बस पलटकर 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 40 से ज्यादा यात्री गंभीर घायल हैं। इनमें छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। पुलिसवाले बच्चों को गोद में लेकर एंबुलेंस में बैठाते नजर आए।

फायर ब्रिगेड के मुताबिक, बिहार नंबर की लग्जरी बस राजस्थान के भिवाड़ी से छपरा (बिहार) जा रही थी। सभी लोग छठ पर्व के लिए अपने-अपने घर जा रहे थे। हादसा जिला मुख्यालय से करीब 30 किमी दूर पारा थाना क्षेत्र में जीरो पॉइंट पर हुआ।

50 से ज्यादा पुलिसकर्मी और SDRF की 2 टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। शुरूआती जांच में हादसे की वजह टायर फटना बताई जा रही है। घायलों में महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़ के साथ बिहार के कई लोग भी शामिल हैं।

यात्री पंकज शर्मा ने कहा- ड्राइवर नशे में था। उसने 10 मिनट भी बस नहीं चलाई थी कि पलटा दी। लोकबंधु अस्पताल में भर्ती यात्री विकास कुमार ने कहा- ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। बस गिरने से मुझे, मम्मी-पापा को चोट लगी है।

पारा थाना पुलिस के अनुसार, कुल 50-55 यात्री बस में सवार थे। इनमें 45 बुरी तरह घायल हुए हैं। जिन 3 यात्रियों की मौत हुई, उनमें 2 की शिनाख्त हुई है, 1 मृत पुरुष की पहचान नहीं हो पाई है। मरने वालों में छपरा के शंकर रज्जक (63) और शामली राय (43) के साथ एक अज्ञात भी है।लोकबंधु अस्पताल के उटर डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव ने कहा- सुबह 7 बजे के आसपास हादसे की सूचना मिली थी। अस्पताल में एक-एक कर घायलों की संख्या बढ़ती गई। 32 घायल यहां पर लाए गए, जिनमें 2 ब्रॉट डेड थे।

बचे हुए 30 घायलों में जिनके सिर, रीढ़ में गंभीर चोटें थीं, उन्हें KGMU के लिए रेफर कर दिया गया। इस समय लोकबंधु में 25 घायल भर्ती हैं। इनकी प्रॉपर देखभाल की जा रही है।

लोकबंधु अस्पताल के उटर डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव हर घायल की निगरानी कर रहे हैं। लोकबंधु अस्पताल में भास्कर रिपोर्टर शिवा मिश्रा पहुंच हैं। उन्होंने यात्रियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। घायल जितेंद्र यादव ने कहा- बस में 2 ड्राइवर थे। जिस ड्राइवर ने रात में बस चलाई, वह सुबह 7 बजे के आसपास सोने चला गया। उसकी जगह सो रहा ड्राइवर बस चलाने लगा। इसके बाद 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, यह हादसा हो गया। बस का फिटनेस 5 अगस्त 2027 तक वैध है। एंश्योरेंस 31 जुलाई 2027 तक और पॉल्यूशन 6 अगस्त 2027 तक वैध है। 2 दिसंबर 2030 तक बस की परमिट है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, ट्रॉमा के बाद लोकबंधु अस्पताल भी पहुंच गए हैं।

दिल्ली में दिवाली के अगले दिन पांच साल में सबसे खराब हवा

कितने बिगड़ सकते हैं हालात, वजह क्या?



नई दिल्ली(एजेंसी)। दिवाली के बाद की सुबह काफी धुंध भरी रही। स्मॉग का असर ऐसा रहा कि जहां सड़कों पर दृश्यता (विजिबिलिटी) कफी कम हो गई तो वहीं आम लोगों को आंखों और गले में जलन की स्थिति का सामना करना पड़ा। दिल्ली में सोमवार को इस स्थिति के पीछे दिवाली पर एक घंटे तक आतिशबाजी को माना जा रहा है। हालांकि, अगर बीते कुछ दिनों के आंकड़ों को उठाया जाए तो सामने आता है कि दिवाली की आतिशबाजी का असर इस साल उतना नहीं रहा, जितना अन्य दिनों में हुआ है। दिवाली की रात नियमों का उल्लंघन कर देर रात तक छोड़े गए पटाखों के कारण दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचा है। 1. वायु गुणवत्ता और एक्यूआई की स्थिति औसत एक्यूआईः दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 370 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। मौसम वैज्ञानिकों और चेतावनी प्रणाली के मुताबिक, इसके दिन में और बिगड़कर गंभीर श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है।निगरानी प्लेटफॉर्म्स के आंकड़ेः ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म AQI.in के मुताबिक, दिवाली के बाद दिल्ली का एक्यूआई 2,283 तक चढ़ गया था और सुबह यह 637 पर दर्ज किया गया, जिसे खतरनाक (hazardous) माना गया। रविवार और दिवाली की रातः दिवाली के दिन शहर का औसत एक्यूआई 376 रहा था। दिवाली की रात 59 निगरानी स्टेशनों में से 20 स्टेशनों पर हवा गंभीर (Severe) श्रेणी में दर्ज हुई थी।स्विट्जरलैंड के वायु गुणवत्ता मापने वाले प्लेटफॉर्म आईक्यूएयर (IQAir) के मुताबिक, हवा में सूक्ष्म कणों (पीएम2.5) की सांद्रता 170 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वार्षिक दिशा-निर्देशों से लगभग 34 गुना ज्यादा है। पीएम2.5 सबसे प्रमुख चिंताजनक प्रदूषक रहा, क्योंकि यह फेफड़ों में गहराई तक जाकर रक्तप्रवाह में प्रवेश करने में सक्षम होता है।

दीपावली पर आतिशबाजी का कहर : जूता फैक्ट्री सहित 12 जगह अग्निकांड

आगरा, एजेंसी। उत्तरप्रदेश के आगरा में दीपावली की खुशियां इस बार आतिशबाजी की चिंगारियों की चपेट में आकर तबाही में बदल गईं। रविवार की रात से सोमवार सुबह तक ताजनगरी में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर भीषण आग लगने की दर्दनाक घटनाएं सामने आईं, जिसमें जूता कारखाने, फलों की दुकानें और रिहायशी मकान शामिल हैं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पूरी रात लगातार आग बुझाने में जुटी रही, जिससे शहर में दहशत का माहौल बना रहा। आग की सबसे बड़ी घटना लक्ष्मी नगर में हुई, जहां पटाखों से निकली एक चिंगारी ने एक जूता कारखाने में आग लगा दी। कारखाने में रखे केमिकल और चमड़े के सामान के कारण आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर गई। ऊंची उठती लपटों ने पूरे इलाके में भय का माहौल पैदा किया। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। हालांकि, तब तक कारखाने का भारी नुकसान हो चुका था। इसके अलावा, बिचपुरी रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक फलों की दुकान भी भीषण आग की चपेट में आ गई। आग इतनी तेज थी कि पूरी दुकान जलकर राख हो गई, जिससे व्यापारी का लाखों का सामान नष्ट हो गया। वहीं, आवास विकास कॉलोनी में भी एक मकान आतिशबाजी की वजह से लगी आग से प्रभावित हुआ, जिसे दमकल कर्मियों ने समय रहते नियंत्रित कर लिया। दीपावली की रात शहर भर से आग लगने की लगातार सूचनाएं मिलती रहीं, जिसके चलते दमकल विभाग की गाड़ियां पूरी रात एक के बाद एक घटनास्थल पर दौड़ती रहीं। गनीमत यह रही कि इन दर्दनाक हादसों में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपये के माल के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसने दीपावली की खुशियों को मातम में बदल दिया।

काली पूजा पर कोलकाता पुलिस का बड़ा एक्शन : 592 गिरफ्तार

कोलकाता, एजेंसी। कोलकाता में काली पूजा की रात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोलकाता पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान कुल 592 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 205 ने प्रतिबंधित पटाखे जलाए थे, जबकि 387 को उपद्रव करने के आरोप में पकड़ा गया। इसके साथ ही, पुलिस ने 238.6 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे भी जब्त किए। पुलिस कार्रवाई केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 593 लोगों पर भी कार्रवाई की गई। इसमें 454 बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालक और यात्री, 75 तेज व लापरवाही से वाहन चलाने वाले और 64 शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले शामिल थे। इसके अतिरिक्त, 6 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।

एक सोची-समझी साजिश के चलते पंजाब के खेतों में जानबूझकर लगाई गई आग

- दिल्ली में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंचा, मंत्री कपिल मिश्रा ने लगाए आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। दीपावली के मौके पर तय समयसीमा के काफी बाद तक राजधानी दिल्ली में बड़े पैमाने पर पटाखे जलाए जाने के कारण सोमवार को शहर की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया। सुबह जब लोगों की आंखें खुलीं, तो पूरा शहर घनी धूसर धुंध की चादर में लिपटा हुआ था। इस बीच दिल्ली की रेखा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इसे एक बड़ी साजिश बताया है और इसका संबंध पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं से जोड़ा है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने मीडिया से कहा कि रविवार शाम उन्हें पंजाब के किसानों के फोन आने लगे थे, जिन्होंने बताया कि रात के समय उनके खेतों में जानबूझकर आग लगाई जा रही है।

शाह ने अहमदाबाद में इस्कॉन-साणंद एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया, ट्रैफिक से मिलेगी राहत



अहमदाबाद , एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 4.03 किलोमीटर लंबे इस्कॉन-साणंद एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 464 करोड़ रुपये की भारी लागत से निर्मित यह छह-लेन परियोजना अहमदाबाद के सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने और सरखेज व गांधीनगर के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

नेशनल हाईवे 147 पर स्थित यह कॉरिडोर इस्कॉन जंक्शन को साणंद फ्लाईओवर से जोड़ता है, जिससे कर्णावती क्लब, प्रहलाद नगर और वाईएमसीए जैसे व्यस्त इलाकों से गुजरने वाले वाहनों की आवाजाही बहुत आसान होगी। यह एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य शहरी गतिशीलता को सुगम बनाना है। इस परियोजना से यात्रियों के यात्रा समय में महत्वपूर्ण बचत होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 26.8 मीटर चौड़ा यह एलिवेटेड कॉरिडोर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए 5,880 मीटर के हिस्से में विशेष नॉइज बैरियर (शोर रोकने वाली दीवारें) लगाए गए हैं, जो आसपास के आवासीय क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत प्रदान करेंगे। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इसमें 297 स्ट्रीटलाइट्स, एक एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, रोड साइनबोर्ड, कैट्स आई और चकाचौंध रोकने वाले (एंटी-ग्लेयर) उपाय शामिल हैं, जो रात में ड्राइविंग को सुरक्षित और आरामदायक बनाएंगे। मुख्य कॉरिडोर के अलावा, ट्रैफिक की आवाजाही को और भी आसान बनाने के लिए 7 से 14 मीटर चौड़ी व्हाइट-टॉपिंग सर्विस सड़कें भी बनाई गई हैं। उम्मीद है कि यह कॉरिडोर सरखेज और गांधीनगर के बीच आवागमन करने वालों को अधिक सुरक्षित और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे हाईवे पर लगने वाले भीषण जाम से प्रभावी ढंग से निजात मिलेगी और अहमदाबाद के निवासियों के जीवन में सुधार आएगा। इस महत्वपूर्ण उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, शहरी विकास राज्य मंत्री दर्शना वाघेला, अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट, विधायक अमित ठाकर और बाबूभाई पटेल सहित अहमदाबाद नगर निगम के पदाधिकारी, स्थानीय पार्षद और कई सामाजिक व राजनीतिक नेता भी उपस्थित रहे, जो इस परियोजना के महत्व को दर्शाता है।

किसी की इबादतगाह शहीद की जाए तो हर इंसान का दिल पसीज जाएगा, आंसू आ जाएंगे

- बाबरी मस्जिद विध्वंस पर सोनिया गांधी के बयान पर अबू आजमी का भावनात्मक बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के हालिया बयान ने एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर दी है। सोनिया गांधी ने दावा किया था कि जब उन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस की खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। इस बयान के बाद बीजेपी लगातार सोनिया गांधी पर हमलावर है। इसी बीच महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी का बड़ा और भावनात्मक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी के आंसुओं की कद्र तो की, लेकिन अपनी और अपने समुदाय की पीड़ा को भी व्यक्त किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अबू आजमी ने सोनिया गांधी के आंसुओं को सम्मान देते हुए कहा कि हर सच्चा इंसान, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, अगर किसी की इबादतगाह शहीद की जाए और गुंडागर्दी के बलबूते पर हथौड़ा लेकर उसे तोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि हर इंसान का दिल पसीज जाएगा और उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों द्वारा बाबरी मस्जिद को शहीद करने की कड़ी निंदा की और कहा कि इससे बुरा कोई काम हो ही नहीं सकता है। आजमी ने सोनिया गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सोनिया गांधी के आंखों में आंसू थे, हम सब तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे उस दिन। हमारी मस्जिद को इन लोगों ने शहीद कर दिया और आज उसपर मंदिर बना दिया। उनके इस बयान में उस दिन की प्रत्यक्ष पीड़ा और गहरी भावनाएं स्पष्ट रूप से झलकती हैं, जो एक समुदाय के तौर पर उन्होंने महसूस की थी। इतना ही नहीं अबू आजमी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट ने यह बोलकर मंदिर बनाने की इजाजत दी थी कि बहुसंख्यक ऐसा चाहते हैं। मुसलमान हिंदुस्तान में हमेशा से माइनॉरिटी में है।

अखिलेश का अयोध्या दौरा- पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने किया स्वागत

लखनऊ , एजेंसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना है। इस बहुप्रतीक्षित दौरे को लेकर जहां सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, वहीं बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया है। अंसारी ने कहा कि भगवान राम की नगरी में सभी को दर्शन करने आना चाहिए। उन्होंने अयोध्या के धार्मिक महत्व पर जोर देकर कहा, यह धर्म की नगरी है, भगवान राम और हनुमान का निवास स्थान है। यहां बहने वाली सरयू नदी और प्राचीन परंपराएं देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं। अंसारी ने अपनी टिप्पणी में अयोध्या की धरती पर हर गलती को क्षमा किए जाने की बात कहकर अखिलेश के दौरे को सद्भावपूर्ण दृष्टिकोण से देखने का संकेत दिया, जहां उनका मानना है कि भगवान सभी के लिए हैं और सभी को उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अखिलेश के कदम को सीधे तौर पर चुनावी रणनीति का हिस्सा बताकर हमलावर है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान कारसेवकों पर हुई गोलीबारी का मुद्दा फिर से उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया देकर कहा है कि अखिलेश अयोध्या आएं, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने पुराने कृत्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय ने दावा किया था कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। इस प्रकार, अखिलेश का यह अयोध्या दौरा राजनीतिक बहसों का केंद्र बना हुआ है, जिसमें स्वागत और तीखी आलोचना दोनों एक साथ चल रही हैं।

खुशियों की ईद बयान पर घमासान, सोनिया और राहुल गांधी के मुखपत्र खरगे

गिरिराज सिंह सहित कई नेताओं ने लगाया अल्पसंयक तुष्टीकरण का आरोप

नई दिल्ली , एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिवाली को खुशियों की ईद बताने वाले बयान ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई नेताओं ने बयान की कड़ी निंदा कर कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और हिंदू विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस ने बयान को धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बताया।

केंद्रीय मंत्री सिंह ने खरगे के बयान को राहुल गांधी और गांधी परिवार के मुखपत्र की टिप्पणी करार दिया। सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दशकों से देश में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिसकी शुरुआत नेहरू ने देश के विभाजन से की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटने और मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करती है, जबकि हिंदू त्यौहारों पर उनकी जुबान पर चार अच्छी लाइनें भी नहीं होती और न ही वे कोई अच्छी बात कहते हैं।

बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने खरगे के बयान को गांधी परिवार के इशारे पर सोची-समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इतनी अंधी हो गई है कि वह प्रकाश के पावन पर्व पर भी तुष्टीकरण कर रही है और उसके नेताओं के बयानों में हिंदू-विरोध का जहर खुलकर सामने आ रहा है। बिहार बीजेपी नेता सरावगी ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस में किसी और त्यौहार को खुशियों की दीपावली कहने की हिम्मत है? उन्होंने इन बयानों को 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश करार दिया।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस को सनातन-विरोधी और हिंदू-विरोधी पार्टी बताकर कहा कि यह पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति है। बीजेपी प्रवक्ता भंडारी ने सोनिया गांधी के बाबरी और बाटला एनकाउंटर पर कथित रूप से रोने का जिक्र कर आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। उन्होंने बताया कि गांधी-वाड्रा परिवार या खरगे में से कोई भी अयोध्या के राम मंदिर नहीं गया और उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया कहे जाने पर भी कांग्रेस चुप रही थी।

दूसरी ओर, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बयान का बचाव किया। अल्वी ने समझाया कि ईद खुशी का प्रतीक है और अक्सर इस एक रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ईद का चांद होना मुहावरा खुशी व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है। उन्होंने कहा कि अगर खरगे ने ऐसी बात कही है, तब यह एक ऐसी भावना है जो कि केवल एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति ही व्यक्त कर सकता है, और भाजपा या सांप्रदायिक सोच रखने वाले लोगों से ऐसी भावनाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती।



वायु प्रदूषण से 20 लाख मौतें: फिक्की रिपोर्ट से टारगेट में मोदी सरकार

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने साधा निशाना

नई दिल्ली , एजेंसी। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश दिवाली के बाद देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर मोदी सरकार पर हमलावार है। उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और एक हालिया विस्तृत रिपोर्ट का हवाला देकर दावा किया कि मोदी सरकार देश में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों की गंभीरता को लंबे समय से नजरअंदाज करती रही है।

कांग्रेस नेता रमेश ने बताया कि मोदी सरकार ने अतीत में संसद के अंदर और बाहर कई रिपोर्टों को यह कहकर खारिज किया कि वे भारत के संदर्भ में नहीं हैं या वायु प्रदूषण से सीधी जुड़ी नहीं हैं। हालांकि, फिक्की की यह नई रिपोर्ट इन दावों को पूरी तरह से खारिज करती है। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में भारत में लगभग 20 लाख मौतें जो कुल मौतों का लगभग 22 प्रतिशत है, सीधे तौर पर वायु प्रदूषण के कारण हुईं। यह आंकड़ा देश में स्वच्छ हवा के अभाव के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों को दिखाता है।

कांग्रेस नेता रमेश ने विश्लेषण को गहरी नींद में सोई मोदी सरकार के लिए एक और चेतावनी करार दिया। उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की तुलना सांस लेने में आसानी से करते हुए कहा कि साफ हवा एक कहीं अधिक बुनियादी आवश्यकता है, इस प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि पीएम 2.5 (पार्टिकुलेट मैटर 2.5) का स्तर भारत के कई हिस्सों में जानलेवा खतरे का रूप ले चुका है, जिस पर तत्काल राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है।

प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस नेता रमेश ने तीन-सूत्रीय कार्यक्रम भी साझा किया। उन्होंने कहा कि सुधार का एजेंडा काफी समय से स्पष्ट है और फिक्की की यह रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई के लिए 10 साल का एक जरूरी और चरणबद्ध रोडमैप पेश करती है। इस पर अमल तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। पहला बिंदु, पीएम 2.5 और ओज़ोन के मौजूदा मानकों को सख्त कर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा सुझाए गए सुरक्षित स्तरों के बराबर लाना है। दूसरा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में बदलाव कर विशेष रूप से पीएम 2.5 और ओज़ोन पर केंद्रित करना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की जगह एक नया स्वच्छ वायु अधिनियम लाना, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्रित हो, क्योंकि अब वायु प्रदूषण के स्रोतों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को लेकर कई नए और ठोस सबूत सामने आ चुके हैं।



जम्मू अग्निकांड: महबूबा मुफ्ती ने की व्यापारियों के लिए वित्तीय सहायता की मांग



जम्मू, एजेंसी । पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के आग से तबाह हुए नेहरू बाजार का दौरा किया। उन्होंने अग्निकांड में भारी नुकसान झेलने वाले व्यापारियों के लिए राज्य सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की जोरदार मांग की। शहर के बिक्रम चौक स्थित ऐतिहासिक थोक बाजार में रविवार देर रात लगी भीषण आग में कई दुकानें जलकर खाक हो गईं, इससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

नेहरू बाजार, जो जम्मू के सबसे पुराने कारोबारी केंद्रों में से एक है, अनाज, खाद्य तेल, दाल, आटा, चावल, घी, सूखे मेवे और अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक कारोबार का प्रमुख केंद्र है। दीपावली जैसे त्यौहारों के मौसम में लगी इस आग ने व्यापारियों की खुशियां छीन लीं, जिससे उनकी दिवाली एक अंधेरी और डरावनी रात में बदल गई।

प्रभावित व्यापारियों के प्रति एकजुटता जताकर पूर्व सीएम महबूबा ने कहा कि उमर सरकार की वित्तीय सहायता के बिना वे न इस अपूरणीय क्षति से उबर पाएंगे और न ही अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें से अधिकांश छोटे कारोबारी हैं जिन्होंने अपना काम शुरू करने के लिए कर्ज लिया है या अपने परिवार के गहने तक बेच दिए हैं। वे अपनी दैनिक कमाई से अपने परिवारों का पालन-पोषण करते हैं, और अब उनका सब कुछ तबाह हो गया है। उन्होंने त्यौहारों के मौसम में बाजारों में पर्याप्त सुरक्षा और अग्निशमन इंतजाम न होने पर भी सवाल उठाए।

प्रभावित व्यापारियों ने भी अग्निशमन व्यवस्था में खामियों का आरोप लगाया। उनका कहना था कि आग लगने के शुरुआती पलों में पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, और छोटा दमकल वाहन देरी से और कम पानी के दबाव के साथ पहुंचा। उन्होंने करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया और बताया कि कुछ दुकानदारों का बीमा हो सकता है, लेकिन किसी ने भी इतनी बड़ी तबाही की आशंका नहीं जाहिर थी। यह दो सप्ताह में जम्मू में आग लगने की दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 25 अक्टूबर की रात शिव मार्केट में भी भीषण आग लगी थी, जिसमें 40 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं थीं। इन घटनाओं ने त्यौहारों के मौसम में बाजारों की सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मुंबई के राम मंदिर में तोड़फोड़ और धमकी, दो गिरफ्तार; राजनीतिक संरक्षण की जांच की मांग

मुंबई , एजेंसी । मुंबई के अंधेरी पूर्व स्थित मरोल नाका के राम मंदिर में घुसकर बजरंगबली के पोस्टर फाड़ने, मंदिर के बोर्ड पर काले रंग का स्प्रे पेंट करने और सुरक्षा गार्ड को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो आरोपी अमित पाठक और विनोद मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। मंदिर के ट्रस्टी जयेश पटेल की शिकायत पर आरे पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार, 4 नवंबर, 2026 को पाठक ने 7 नवंबर को मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती की अपील की थी, जिसके बाद उसी दिन शाम को करीब 30-40 लोग मंदिर परिसर में जमा हुए। आरोप है कि इस दौरान पाठक ने सुरक्षा गार्ड नंदलाल केवट के साथ गाली-गलौज की और उसका कॉलर पकड़कर तुझे काटकर जंगल में फेंक देंगे, जैसी जान से मारने की धमकी दी।

कोसी में बाढ़ नियंत्रण को मिलेगी नई दिशा, सुपौल में बना देश का दूसरा मॉडलिंग सेंटर

सुपौल, एजेंसी । बिहार में बाढ़ और नदी कटाव की समस्या के वैज्ञानिक समाधान की दिशा में बड़ी पहल हुई है। सुपौल जिले के वीरपुर में 106 करोड़ की लागत से देश का दूसरा अत्याधुनिक फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन करने की संभावना है। उद्घाटन समारोह की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सावन कुमार ने सोमवार को सेंटर परिसर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, तकनीकी सुविधाओं, रिसर्च बेसिन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मॉडलिंग सेंटर के मुख्य अभियंता को उद्घाटन से पहले सभी लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। डीएम ने स्पष्ट किया कि आयोजन से पहले परिसर की व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने बताया कि इस केंद्र की स्थापना कोसी सहित उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के जल प्रबंधन, बाढ़ के सटीक पूर्वानुमान, तटबंधों की सुरक्षा और नदी के जलप्रवाह एवं दिशा परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई है। इससे बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोकने के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी।

विश्व बैंक के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से निर्मित यह केंद्र पुणे स्थित सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस) के बाद देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है। यहां नदियों के भौतिक मॉडल तैयार कर वास्तविक परिस्थितियों में जलप्रवाह, कटाव और नदी की बदलती धारा का अध्ययन किया जा सकेगा। इससे जल संसाधन विभाग को योजनाओं के निर्माण और तकनीकी निर्णय लेने में वैज्ञानिक आधार मिलेगा। संभावित उद्घाटन कार्यक्रम को देखकर डीएम ने परिसर के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने जंगली घास और झाड़ियों की सफाई, प्रशासनिक भवनों की रंगाई-पुताई, आंतरिक सड़कों की मरम्मत तथा छायादार एवं फलदार पौधे लगाकर ग्रीन बेल्ट विकसित करने का निर्देश दिया।

जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत 11 से 18 नवंबर तक समाज, भाजपा और सरकार मिलकर करेंगे विभिन्न आयोजन : हेमंत खण्डेलवाल

भाजपा की जनजातीय समाज के प्रति प्रतिबद्धता सरकार की योजनाओं में स्पष्ट दिख रही है : सीएम

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल एवं मध्यप्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री मती संपतिया उइके ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की जंयती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 'जनजातीय गौरव सप्ताह' को लेकर पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को जबलपुर, 15 को धार और 16 को खण्डवा में बड़े आयोजन किए जाएंगे। जनजातीय समाज को सम्मान देकर भाजपा ने जो कहा था करके दिखाया है। भाजपा ने मध्यप्रदेश में जनजातीय समाज में राजनैतिक नेतृत्व विकसित किया है। भाजपा की जनजातीय समाज के प्रति प्रतिबद्धता सरकार की योजनाओं में स्पष्ट दिख रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज में स्वाभिमान और स्वतंत्रता की अलख जगाई है। 25 वर्ष की आयु में आदिवासी अस्मिता को बचाने और देश को आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान देने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 11 से 18 नवंबर तक 'जनजातीय गौरव सप्ताह' मनाया जाएगा। इस सप्ताह के तहत भाजपा संगठन समाज और सरकार के साथ मिलकर जनजातीय नायकों के समाज में योगदान, गौरवशाली विरासत, लोककला और संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। भाजपा प्रदेश के सभी जिलों में भव्य सांस्कृतिक जुलूस निकालेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच व समाज के प्रति प्रतिबद्धता संगठन और सरकार की



योजनाओं में दिखाई देती है, वहीं कांग्रेस ने जनजातीय समाज को कभी सम्मान नहीं दिया। भाजपा शासन की योजनाओं और संगठन के कार्यों के माध्यम से समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सामने रखती है। मध्यप्रदेश देश में सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाले राज्यों में शामिल है। भाजपा ने मध्यप्रदेश में जनजातीय समाज में अपना राजनीतिक नेतृत्व भी विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मध्यप्रदेश से जनजातीय समाज के दो मंत्री दुर्गादास उइके एवं मती सावित्री ठाकुर हैं। मध्यप्रदेश सरकार में जनजातीय समाज से मती निर्मला भूरिया, मती संपतिया उइके, विजय शाह, नागर सिंह चौहान एवं मती राधा सिंह मंत्री हैं। भगवान बिरसा मुंडा को एक आदर्श जननायक के रूप में देश भर में प्रतिष्ठित करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस को मनाने के साथ भाजपा संगठन और सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी के विचार को आगे बढ़ाते हुए यह कल्पना की गई है कि हमारे नायकों और आदिवासी जननायकों को उनके नाम, उनकी जयंती और उनके बलिदान दिवस के माध्यम से स्मरण किया जाए। भारत में जयंती मनाकर उनके योगदान को स्मरण करना देश की संस्कृति का हिस्सा है। हम इसे कभी समाजों को अलग-अलग करके नहीं देखते। उन्होंने कहा कि हमारा जनजातीय समाज इतना बड़ा है, उसका योगदान बहुत व्यापक है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने उन अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, जिनके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। बिहार और झारखंड के क्षेत्र में उन्होंने जो संघर्ष किया, वह देश के गौरवशाली इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उसी के समकालीन मध्यप्रदेश में टंट्या मामा ने अंग्रेजों के विरुद्ध योजना बनाकर संघर्ष किया और देश के लिए अपना बलिदान दिया। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, और रानी दुर्गावती ने अपना बलिदान देश के लिए दिया है। हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट जबलपुर में रानी दुर्गावती के सम्मान में की, इसके बाद दमोह जिले के संग्रामपुर में की। पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह के सम्मान में कैबिनेट की बैठक की गई। हमारी सरकार ने जनजातीय नायकों को सम्मान देते हुए रानी दुर्गावती के नाम पर अन्न योजना शुरू की। टंट्या मामा के नाम पर खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया। राजा शंकर शाह व रघुनाथ शाह के नाम पर मंडला मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। यह भाजपा सरकार की जनजातीय समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि उसने जनजातीय समाज के सम्मान के लिए क्या किया। कांग्रेस ने जनजातीय समाज के लिए कोई कार्य नहीं किया है।



जनसुनवाई में 54 आवेदन प्राप्त हुए

जनसुनवाई में अधिकारियों ने सुनी आवेदकों की समस्याएं

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी ने मंगलवार को जिले से जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। जनसुनवाई में आए नागरिकों से 54 आवेदन प्राप्त हुए। इस मौके पर एडीएम, एसडीएम एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सीईओ मती इला तिवारी ने जनसुनवाई में आए हर एक आवेदक से धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशील रूख अपनाते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों की समस्याओं पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।



भोपाल जिले की सभी ग्राम पंचायतों में अवैध शराब पर रहेगी सतत निगरानी

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जारी किए निर्देश, अवैध बिक्री की सूचना तत्काल मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी को दें

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

जिले की सभी ग्राम पंचायतों में अवैध और कच्ची शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए ग्राम स्तर पर सतत निगरानी की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रियंक मिश्रा ने 5 नवंबर 2026 को जारी आदेश में संबंधित मैदानी अमले को निर्देश दिए हैं कि गांव में अवैध शराब की बिक्री की जानकारी मिलते ही तत्काल सूचना दें।

आदेश के अनुसार, गांव में कच्ची या अवैध शराब की बिक्री, लाइसेंसी दुकान से पैकारी, अथवा एजेंट, डायरी या किसी अन्य माध्यम से अवैध बिक्री की जानकारी मिलने पर निकटतम अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी में से जो भी सबसे नजदीक हो, उसे तत्काल सूचित किया जाए।

ये निर्देश ग्राम पंचायत सचिवों, पटवारियों, ग्राम पटेलों, कोटवारों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम को दिए गए हैं। कलेक्टर ने आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के निर्देशों के क्रम में जारी आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 34(1) के तहत सूचना देने के दायित्व का भी उल्लेख किया है।

संजय गांधी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कई आधुनिक सुविधाओं का किया लोकार्पण

रीवा को मेडिकल हब के रूप में किया जा रहा विकसित : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

विंध्य क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊँचाई देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के संजय गांधी अस्पताल, जीएमएच और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कई अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं और सेंटरों का लोकार्पण किया। इन सुविधाओं के शुरू होने से रीवा और आसपास के जिलों के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब बड़े महानगरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जटिल रोगों का इलाज अब रीवा में संभव हो गया है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने संजय गांधी हास्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए लगभग 6.5 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक नेट मशीन का लोकार्पण किया। इस मशीन के आने से एचआईवी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी गंभीर बीमारियों का विंडो पीरियड संक्रमण का शुरुआती दौर में पता लग जाएगा। इस जाँच में पहले 15 दिन से 1 महीने लगते थे जो अब दो दिन में हो जाएगी। इससे कोई भी संक्रमित रक्त किसी स्वस्थ मरीज को नहीं चढ़ पाएगा। सामान्य सेपरेशन यूनिट से जहाँ मरीज के शरीर में 5,000 प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, वहीं इस आधुनिक मशीन से सीधे 50,000 तक प्लेटलेट्स बढ़ाए जा सकते हैं। नवजात शिशुओं के जीवन रक्षा और बेहतर पोषण के लिए जीएमएच अस्पताल के बाल शिशु विभाग में एक आधुनिक मिल्क बैंक की शुरुआत की गई है। जिन माताओं को पर्याप्त दूध नहीं मिल पाता, उनके नवजात शिशुओं को इस बैंक के माध्यम से पॉश्चराइज्ड मिल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और न्यूरोलॉजिकल विकास बेहतर ढंग से हो सकेगा। एनएचएम के सहयोग और





डॉ. नरेश बजाज की टीम के प्रयासों से यह सुविधा उपलब्ध हुई है। बढ़ते मरीजों के दबाव और गंभीर रोगियों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आईसीयू सुविधाओं का विस्तार किया गया है। हार्ट आईसीयू 10 बेड से बढ़ाकर 20 बेड कर दिया गया है। नेफ्रोलॉजी आईसीयू 5 बेड से बढ़ाकर 10 बेड में परिवर्तित किया गया है। बच्चों के विशेष स्वास्थ्य और गंभीर रोगों के इलाज के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। मंदबुद्धि या संवाद में असमर्थ बच्चों के लिए आरईआईसी केंद्र का लोकार्पण किया गया है, जहाँ 5,000 से अधिक पंजीकृत बच्चों को ओपीडी और फिजियोथेरेपी के जरिए नियमित मार्गदर्शन व देखभाल मिलेगी। बच्चों में कैंसर के समय पर कीमोथेरेपी और इलाज के लिए विशेष डे केयर यूनिट शुरू की गई है। कैनकिट संस्था के साथ एमओयू किया गया है जो कैंसर पीड़ित बच्चों के आने-जाने का पूरा खर्च वहन करेगी। इसके साथ ही, आगामी दो महीनों के भीतर रीवा में ही पेट सीटी मशीन भी स्थापित होने जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज, संजय गांधी, जीएमएच और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। चिकित्सकों की पूरी टीम के समन्वित प्रयासों से रीवा को एक बेहतरीन मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि क्षेत्र के मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। कार्यक्रम के दौरान डीन डॉ. शशिधर गर्ग, अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल डॉ. प्रियंक शर्मा, डॉ. नरेश बजाज, डॉ. मनोज इंदुरकर और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अक्षय वास्तव तथा अन्य डॉक्टर उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई

विदिशा और धार में 1 करोड़ 19 लाख रुपये से अधिक कीमत का गांजा एवं गांजे के पौधे जप्त

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से मादक पदार्थों की अवैध खेती, तस्करी एवं कारोबार के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा ऐसे अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ मादक पदार्थों की खेती और सप्लाई नेटवर्क पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में विदिशा और धार जिले में पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों में कुल 467.328 किलोग्राम गांजा एवं गांजे के हरे पौधे जप्त किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 19 लाख 13 हजार रुपये है। दोनों मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले में पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के निर्देशन में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत थाना करारिया चौराहा पुलिस ने ग्राम ब्योची में कार्रवाई कर 104.14 किलोग्राम



गांजा जप्त किया। इसकी अनुमानित कीमत 52 लाख रुपये है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर गांजा जप्त किया तथा एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जिले में पुलिस अधीक्षक धार श्री सचिन शर्मा के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना टाण्डा पुलिस ने ग्राम पुरा में कपास के खेत के बीच की जा रही गांजे की अवैध खेती का खुलासा किया। पुलिस टीम ने खेत से गांजे के 383 हरे पौधे जप्त किए, जिनका कुल वजन 363.188 किलोग्राम तथा अनुमानित कीमत 67 लाख 13 हजार रुपये है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी से गांजे की खेती के स्रोत, संभावित सप्लाई और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध निरंतर चलाए जा रहे अभियानों के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध खेती, भंडारण एवं तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

57 जिला स्तरीय ब्लड सेंटर्स को हब सेंटर्स से किया गया मैप

प्रदेश के 5 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में एनएटी जाँच सुविधा प्रारंभ

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

प्रदेश में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए एनएटी जाँच सुविधा का विस्तार किया गया है। पूर्व में यह सुविधा प्रदेश के केवल दो हब सेंटर्स तक सीमित थी, जिसे अब विस्तारित कर पाँच संभागों के शासकीय ब्लड सेंटर्स तक उपलब्ध कराया जा रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा स्थित पाँच शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को एनएटी जाँच के हब सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है। इनसे प्रदेश के विभिन्न जिलों के 57 स्पोक ब्लड सेंटर्स को मैप किया गया है। दिनांक 23 अक्टूबर 2026 से सभी पाँच हब सेंटर्स पर ID-NAT मशीनों की स्थापना कर जाँच का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। एनएटी जाँच सुविधा प्रारंभ होने से रक्त में HIV, Hepatitis-B ??? Hepatitis-C जैसे संक्रमणों की पहचान विंडो पीरियड के दौरान भी संभव हो सकेगी। इस तकनीक के माध्यम से संक्रमण की पहचान की



अवधि लगभग 45 दिनों से घटकर 5 दिन तक हो सकेगी। इससे संक्रमित रक्त के ट्रांसफ्यूजन का जोखिम कम होगा तथा मरीजों को अधिक सुरक्षित रक्त एवं रक्त अवयव उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इस सुविधा का विशेष लाभ सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, डायलिसिस एवं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को मिलेगा। इन मरीजों को उपचार के दौरान बार-बार रक्त अथवा रक्त अवयवों की आवश्यकता होती है। एनएटी जाँच के माध्यम से उन्हें संक्रमणमुक्त एवं सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। एनएटी जाँच की संपूर्ण प्रक्रिया आधुनिक एवं उच्च तकनीक आधारित उपकरणों के माध्यम से पूर्णतः स्वचालित रूप से संचालित की जाएगी।

इसके साथ ही नमूनों की ट्रैकिंग, जाँच प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग की निगरानी निर्धारित तकनीकी प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। हब एवं स्पोक मॉडल के माध्यम से एनएटी जाँच सुविधा का विस्तार प्रदेश की रक्ताधान सेवाओं को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उपचार के दौरान सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।

पुलिस संगठन की संरचना, स्वीकृत बल, संसाधनों एवं उपलब्धियों का समग्र विवरण समाहित

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने मध्यप्रदेश पुलिस की 'सांख्यिकी डाटा पुस्तिका-2025' का किया विमोचन

प्रातःकाल एक्सप्रेस, भोपाल

पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा ने आज पुलिस मुख्यालय, भोपाल में मध्यप्रदेश पुलिस की 'सांख्यिकी डाटा पुस्तिका-2025' का विमोचन किया। यह पुस्तिका मध्यप्रदेश पुलिस की संगठनात्मक संरचना, स्वीकृत बल, उपलब्ध संसाधनों एवं कार्यक्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत करने वाला महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज है। इसमें वर्ष 2025 के दौरान पुलिस संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारियों को संकलित कर सुव्यवस्थित एवं सरल स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है।

पुस्तिका में 01 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक की अवधि के आंकड़ों को शामिल किया गया है। इसके नवीनतम संस्करण को अधिक उपयोगी, तथ्यपरक एवं व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से अनावश्यक एवं दोहराव वाले आंकड़ों को हटाकर महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही जटिल सूचनाओं को सरल एवं व्यवस्थित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे पुलिस अधिकारियों एवं अन्य संबंधित इकाइयों को आवश्यक जानकारी सहजता से उपलब्ध हो सकेगी। वर्ष 2025 में मध्यप्रदेश पुलिस के स्वीकृत बल में कुल 2,673 नवीन पदों की वृद्धि हुई है। इनमें तकनीकी सेवाएं (एफएसएल) के 1,266, पुलिस बैंड के 932, हॉक फोर्स के 325 तथा जिला बल उज्जैन के 150 पद शामिल हैं। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में पुलिस के आवासीय परिसरों के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही



उपलब्ध डायल-112 सेवा से संबंधित आंकड़ों को भी अद्यतन किया गया है। पुलिस वाहनों की संख्या वर्ष 2024 में 1,150 थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 1,200 हो गई है। वर्ष 2024 में प्रदेश में कुल 1,173 पुलिस थाने थे। उज्जैन में दो नवीन पुलिस थानों की स्थापना के बाद वर्ष 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 1,175 हो गई है।

डिजिटल संस्करण भी होगा

सांख्यिकी डाटा पुस्तिका का डिजिटल संस्करण मध्यप्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य संबंधित व्यक्ति आवश्यक सांख्यिकीय जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यह सांख्यिकी डाटा पुस्तिका केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश पुलिस की संगठनात्मक क्षमता, उपलब्ध संसाधनों एवं विकास की दिशा को समझने का महत्वपूर्ण आधार है। इसमें संकलित तथ्य नीतिगत निर्णय लेने, संसाधनों के बेहतर उपयोग, आवश्यकताओं के आकलन तथा भविष्य की कार्ययोजनाओं एवं रणनीतियों के निर्धारण में उपयोगी सिद्ध होंगे। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संगठनात्मक विकास, संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन तथा आधुनिक एवं जनोन्मुखी पुलिसिंग को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योजना श्री योगेश चौधरी, पुलिस महानिरीक्षक योजना श्री अभय सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री विनीत कपूर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जलने के बाद के 20 मिनट बेहद कीमती, डॉक्टर से जानें बर्न इंजरी पर तुरंत क्या करें



रसोई में काम करते समय या फिर दीपक जलाते समय कई बार बर्न इंजरी हो जाती है। जलने के बाद अक्सर लोग घबरा जाते हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। यहां डॉक्टर से जानिए पटाखे से बर्न इंजरी पर तुरंत क्या करें और जलने के बाद के 20 मिनट क्यों

अचानक जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो पीड़ित के साथ आसपास के लोग घबरा जाते हैं। दिवाली के मौके पर अक्सर जलने की दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। त्योहार के दौरान खाना बनाते समय गर्म चीजों से हाथ लने, दीपक जलाते समय और पटाखे फोड़ते समय भी कई बार जलने की घटनाएं हो जाती हैं। जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो अक्सर सोचने का मौका भी नहीं मिलता। जब भी जलने की समस्या होती है तो लोग तुरंत बर्फ लगाने या बर्न वाली दवा लगाते हैं लेकिन डॉक्टर इन्हें गलत बताते हैं। प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कंसल्टेंट डॉक्टर अनुपम गोलाश बताते हैं कि जलने के तुरंत बाद जली हुई त्वचा को ठंडा करना और उसे और ज्यादा नुकसान से बचाना होता है। आइए, डॉक्टर से जानते हैं बर्न इंजरी पर तुरंत क्या करना चाहिए।20 मिनट तक पानी के नीचे रखें जली हुई जगहसबसे सही तरीका यह है कि जली हुई जगह को 20 मिनट तक नल के ठंडे बहते पानी के नीचे रखें। इससे प्रभावित हिस्से का तापमान कम होता है और चोट को और बढ़ने से रोका जा सकता है। बस ध्यान रखना है कि पानी ठंडा होना चाहिए, लेकिन बर्फ जैसा ठंडा नहीं। अगर 20 मिनट पूरे होने से पहले ही दर्द कम होने लगे, तब भी पूरे समय तक पानी से ठंडा करना जारी रखें।

ढीली ड्रेसिंग करें

जब जली हुई जगह ठंडी हो जाए, तो सूजन आने से पहले अंगूठियां, घड़ियां या आसपास के कपड़े हटा दें। अगर कोई कपड़ा त्वचा से चिपक गया है, तो उसे खींचकर न निकालें। जली हुई जगह को किसी साफ, बिना रेशे वाले कपड़े (ड्रेसिंग) से ढीले ढंग से ढक दें। इसके अलावा आप उस पर क्लिंग फिल्म यानी प्लास्टिक रैप की एक परत लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि क्लिंग फिल्म को शरीर के किसी हिस्से पर कसकर नहीं लपेटना चाहिए।

नहीं अपनाएं घरेलू उपाय

ताजी जली हुई जगह पर कुछ चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको बर्फ लगाने से पहले से ही घायल त्वचा को और नुकसान पहुंच सकता है। टूथपेस्ट, मक्खन, खाना पकाने का तेल या अन्य घरेलू नुस्खे त्वचा को ठंडा करने में मदद नहीं करते, बल्कि घाव में इंफेक्शन फैला सकते हैं। तुरंत कोई क्रीम या मरहम लगाने से डॉक्टर के लिए चोट की गंभीरता का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। अगर छाले पड़ जाएं, तो उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा करने से अंदर की त्वचा खुल जाती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?

एक्सपर्ट का मानना है कि जली हुई जगह को देखकर उसकी गंभीरता का कुछ अंदाजा तो लग सकता है, लेकिन घर पर इसका सही आकलन करना हमेशा आसान नहीं होता। हल्की जलन में त्वचा लाल हो सकती है और उसमें दर्द हो सकता है। गहरी चोट में छाले पड़ सकते हैं, त्वचा का रंग फीका या मोम जैसा दिख सकता है। कभी-कभी बहुत गंभीर जलन में दर्द कम महसूस हो सकता है, क्योंकि त्वचा की नसें डैमेज हो चुकी होती हैं।

विपक्ष की एकजुट चुनौती और जवाबदेही के सवाल



राहुल हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। वे समाज के वंचित वर्ग के हितों की पैरवी करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन में ऐसे वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और लोकतंत्र की हिफाजत पर जोर दिया है। वे संसद और सड़क दोनों जगह विपक्ष के नेता की असली भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष को एकजुट रखने के लिए आगे आकर प्रयास किए हैं। समाचार पढ़ें चुनाव प्रक्रिया की स्वच्छता बहाल करने के लिए देश में पहली बार बड़े पैमाने पर विरोध के स्वर लगातार उठे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लंबे समय से चुनावों में धांधली का मुद्दा उछाल रही है। अदालतों में भी मुकदमे दायर हुए हैं। 1 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की एकजुट रैली ने चुनावी गड़बड़ी के खिलाफ असरदार संदेश दिया है। इस बीच चुनाव आयोग की कुछ और अनियमितताएं सामने आ रही हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। उनके बचाव की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने संभाल रखी है। हालांकि, मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की प्रक्रिया में खामियों के बारे में वह कुछ नहीं बोलती है।यहां हम दो अहम मुद्दों पर गौर करते हैं- पहला विपक्षी दलों की एकता और दूसरा लोकतंत्र के सामने मौजूद खतरे। एसआईआर में गड़बड़ी के खिलाफ विपक्ष का संयुक्त प्रदर्शन और उसमें छात्रों, एक्टिविस्ट, कुछ अन्य संगठनों की सक्रियता बताती है कि जनता का एक वर्ग इस मुद्दे की गंभीरता से चिंतित है। वह चुनाव आयोग सहित अन्य संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना चाहता है। धांधली के साये में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद के लिए खतरा हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में इससे पहले कभी समूची चुनाव प्रणाली की पवित्रता पर इतना अधिक संदेह नहीं जताया गया था। इसलिए भी विपक्ष की एकजुटता मायने रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 वर्षों के शासनकाल में लंबे समय तक विपक्षी दल अलग-अलग स्वर में बोलते रहे हैं। संसद में जरूर कुछ मुद्दों पर उनके बीच तालमेल नजर आता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस साल अप्रैल में संसद के बजट सत्र में 131 वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित न होने का है। विधेयक में महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं की 33प्रतिशत सीटों के आरक्षण और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के प्रावधान थे। बहरहाल, राज्यों में अपने-अपने हितों की वजह से विपक्षी दल सड़क पर एकजुट नजर नहीं आते थे। लेकिन, सत्ताधारी दल की मिलीभगत से चुनाव आयोग की मनमानी ने बिखरे विपक्ष को एक-दूसरे के साथ खड़ा कर दिया है।रामलीला मैदान के प्रदर्शन में अधिकतर विपक्षी पार्टियों की मौजूदगी दिखाती है कि उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। कई बार अपने अटपटे कथनों के लिए चर्चित रहे राहुल ने मोदी सरकार को कई सामयिक मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया है। गांधी परिवार की विरासत को राहुल के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। वैसे, इस मामले में राहुल कुछ कर भी नहीं सकते हैं। भाजपा के सभी नेता और गोदी मीडिया की उपमा से विभूषित मीडिया का एक वर्ग हमेशा उनकी विशिष्ट विरासत को उछालता रहा है। उन्हें आम आदमी के सरोकारों से बेखबर एक राजपरिवार के वंशज के बतौर पेश किया जाता था। लेकिन राहुल ने लगातार सक्रियता से अपनी इमेज बदली है।राहुल हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। वे समाज के वंचित वर्ग के हितों की पैरवी करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन में ऐसे वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और लोकतंत्र की हिफाजत पर जोर दिया है। वे संसद और सड़क दोनों जगह विपक्ष के नेता की असली भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष को एकजुट रखने के लिए आगे आकर प्रयास किए हैं। पहले कई प्रमुख विपक्षी नेता राहुल का नेतृत्व स्वीकार करने में हिचकिचाते थे। वह हिचक अब बहुत हद तक दूर हो गई है। राज्यों में एक-दूसरे का विरोध करने वालों की एकता व्यावहारिक राजनीति का हिस्सा है। राहुल के राजनीतिक सफर में भारत जोड़ो यात्रा के बाद विपक्ष को एक मंच पर लाने का घटनाक्रम महत्वपूर्ण माना जाएगा। सवाल है, क्या विपक्ष की एकता आगे भी बनी रहेगी। कुछ राज्यों में चुनावी राजनीति के कारण उनके रास्ते जुदा हो जाते हैं। यों भी, भारत में बहुत कम मौकों पर विपक्षी दल एकजुट रहे हैं। सोशलिस्ट नेता राममनोहर लोहिया ने विपक्ष को जोड़ने का नारा उछाला था। 1960 के दशक में कांग्रेस विरोध की राजनीति ने विपक्ष को एक धरातल पर खड़ा किया। राज्यों में कई दलों की संविद सरकारें बनीं। लेकिन ये बेहद अल्पकालिक और अस्थिर साबित हुई थीं। लोहिया का सपना टूट गया। 1977 में इंदिरा गांधी सरकार की इमरजेंसी ने विपक्ष को मिलाया। चार प्रमुख पार्टियों के मेल से जनता पार्टी अस्तित्व में आई। केंद्र में उसकी सरकार भी बनी लेकिन नेताओं की महत्वाकांक्षा और अंतरविरोधों के कारण मोरारजी देसाई की जनता सरकार 28 माह में डूब गई थी। 1989 में विश्वनाथ प्रतापसिंह की जनता दल सरकार भी ज्यादा नहीं टिक पाई थी। वोटर गाइड देखें1970-80 और 1990 के दशक की और वर्तमान स्थितियां पूरी तरह अलग हैं। पहले सत्ता से जुड़े सवाल थे तो अब हेरफेर से चुनाव जीतने और चुनाव आयोग के गलत फैसलों की जवाबदेही तय करने के प्रश्न हैं। संवैधानिक संस्थाओं की साख फिर से कायम करने के मामले में तो विपक्षी दल एकजुट हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने मनमाने तरीके से एसआईआर के जरिये थोक में वोटरों के नाम काटे हैं। अब तक 13 करोड़ से अधिक वोटरों के नाम कट चुके हैं। प्रक्रिया की खामियों का भंडाफोड़ होने के बाद आयोग ने अपने कई फैसले वापस लिए हैं। इनमें फार्म-6 में किए गए विवादास्पद बदलाव, ईसीआईनेट के काम की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने सहित कई फैसले शामिल हैं। दो चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने जिन मुद्दों को उठाया था। उनमें से कुछ में आयोग ने सुधार किए हैं। फिर भी, आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि आयोग के प्रमुख फैसले आम राय से लिए गए हैं।

जबकि संधू और जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से लिखित आपत्ति जताई है कि आयोग के नाम पर उनकी जानकारी के बिना फैसले लिए गए हैं।सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बीच विभिन्न स्तरों पर आयोग के कामकाज में गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं। यहां दो राज्यों उत्तरप्रदेश और कर्नाटक का जिक्र करते हैं। देश की सत्ता की राह तय करने वाले उत्तरप्रदेश में फरवरी, मार्च में विधानसभा चुनाव होंगे। वहां मतदाताओं की संख्या पर विरोधाभास है। राज्य में 1 मार्च 2026 को वयस्कों की अनुमानित संख्या 16.2 करोड़ थी। 2025 में एसआईआर से पहले वोटरों की संख्या 15.4 करोड़ थी। 2026 में एसआईआर के बाद 13.4 वोटर बचे। वहीं स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में वोटरों की संख्या 16.9 करोड़ बताई गई। वोटरों की संख्या में इतना अधिक अंतर समझ में नहीं आता है। पीलीभीत और आजमगढ़ में वोटर लिस्ट में अनियमिताओं की खबरों के बीच उप्र के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा ने पूरे राज्य में फार्म- 6, फार्म- 7 और फार्म- 8 में 10 अप्रैल के बाद कंप्यूटर असिस्टेंट द्वारा की गई प्रविष्टियों का ऑडिट करने के आदेश दिए हैं। पीलीभीत में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटने की खबरें आई हैं। आयोग ने पीलीभीत विधानसभा की मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं के लिए दो चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (ईआरओ) को निलंबित कर दिया है। वोटर गाइड देखें

कर्नाटक में एसआईआर के बाद 99.32 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। अंग्रेजी अखबार हिन्दू में प्रकाशित एक अन्य खबर के अनुसार राज्य में मतदाता सूचियों से नाम काटने के लिए 61 हजार फार्म- 7 चुनाव अधिकारियों ने दाखिल किए हैं। किसी भी आवेदन में नाम हटाने के लिए एक भी कारण नहीं बताया गया है। मतदाता पंजीयन नियम 1960 के तहत नाम हटाने का कारण बताना अनिवार्य है। 23 सितंबर 2026 को दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा खत्म होने के बाद फार्म-7 आवेदनों की संख्या तेजी से बढ़ी। सबसे अधिक फार्म बेंगलुरू महानगर पालिका साउथ डिस्ट्रिक्ट में दाखिल किए गए हैं। यह पता नहीं लग सका है कि नाम हटाने के आवेदनों के बाद कितने नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। पहली नजर में यह अनियमितता है। लेकिन अब तक इसके लिए किसी को दंडित करने की खबरें सामने नहीं आई हैं।

कर्नाटक,उत्तरप्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल सहित कई अन्य राज्यों से भी अनियमतताओं की खबरें आ रही हैं। लेकिन इनके लिए संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में कुछ नहीं हुआ है। कई मामलों से समूची एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितता साबित हो चुकी है। फिर भी, इसके लिए किसी की जवाबदेही तय नहीं की गई है। चुनाव आयोग ने अपनी कई गलतियों और प्रक्रियाओं में सुधार किया है। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। फिर भी, उसके लिए कौन दोषी है। उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। लोकतंत्र में जवाबदेही का सिद्धांत उसके स्वस्थ रहने की प्रमुख शर्त है। यहां तो कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है।

संपादकीय

गिरफ्तारी में पारदर्शिता

किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने और उसकी गिरफ्तारी को दर्शाने के समय को लेकर पुलिसिया कार्रवाई के बारे में अक्सर सवाल उठते रहे हैं। दरअसल, यह व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद, इसकी अनदेखी की जाती रही है। यही वजह है कि अब इस मामले मे देश की शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा है। शीर्ष अदालत का फैसला कहता है कि किसी भी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समय-सीमा, गिरफ्तारी के औपचारिक रिकॉर्ड से नहीं, बल्कि हिरासत में लिए जाने वाले पल से ही शुरू हो जाती है। सही मायने में, यह निर्णय आम भारतीय की संवैधानिक स्वतंत्रता की समयोचित पुष्टि ही है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह फैसला एक स्पष्ट संदेश देता है कि पुलिस मौलिक अधिकारों से बचने के लिये प्रक्रियाओं में हेरफेर नहीं कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 22(2) के उद्देश्य से हिरासत और गिरफ्तारी के बीच किए गए बनावटी अंतर को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक गंभीर खामी को दूर किया है। इस खामी का लाभ उठाकर ही जांच व प्रवर्तन एजेंसियां लोगों को बिना किसी त्वरित न्यायिक निगरानी के हिरासत में रख सकती थीं। दरअसल, नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में हिरासत में लिए गए चार लोगों से जुड़े इस प्रकरण ने, हिरासत में लेने और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच 18 घंटे के अंतराल की विसंगति को उजागर किया है। जिसका कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया था। वास्तव में गिरफ्तारी दिखाने में की गई यह देरी पुलिस को मनमाने ढंग से ताकत के इस्तेमाल और हिरासत में दुर्व्यवहार का मौका देती है। इसमें दो राय नहीं कि अक्सर आरोप लगते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति से मारपीट की गई और लंबी पूछताछ की गई। निस्संदेह, यह स्थिति भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की छवि पर एक सवालिया निशान लगाती है।

हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को न्यायिक जांच के बगैर हिरासत में रखे जाने के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन यह सुरक्षा जांच अधिकारियों के रहमो-करम के भरोसे नहीं रह सकती है। यही वजह है कि देश की शीर्ष अदालत को दो टूक शब्दों में कहना पड़ा कि किसी को हिरासत में लिये जाने की 24 घंटे की समय सीमा में केवल मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाले उचित समय को ही घटाया जा सकता है। यहां उल्लेखनीय है कि मजिस्ट्रेटों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे हिरासत में लिए जाने के वास्तविक समय को ही दर्ज करें। साथ ही यह भी कि वे स्वतंत्र रूप से इस बात की जांच करें कि क्या किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने की प्रक्रिया में संवैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन वास्तविक रूप से किया गया है। इसके साथ ही जरूरी है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण भी स्वतंत्रता के गैर-कानूनी हनन के खिलाफ एक कानूनी प्रभावी उपाय बना ही रहना चाहिए। सही मायने में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में भी न्याय व्यवस्था के लिये एक मार्गदर्शक का कार्य करेगा। जहां अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद के लगभग चार वर्षों में प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती देने वाली दो हजार से अधिक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गई थीं। इस बात में दो राय नहीं हो सकती हैं कि जब कानूनी प्रावधान के क्रियान्वयन में देरी होती है, अथवा जवाबदेही पर्याप्त नहीं होती है, तो संवैधानिक स्वतंत्रता प्रभावहीन होकर रह जाती है। निस्संदेह, किसी भी तरह के अपराध के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, ताकि समाज में कानून का राज्य स्थापित हो सके। लेकिन इसका अर्थ मौलिक अधिकारों को कमजोर करना कदापि नहीं होना चाहिए। बहरहाल, अदालत के निर्देश का सार यह भी है कि पुलिस को कानून के दायरे में रहकर ही कोई भी जांच करनी चाहिए।

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजे ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ स्पष्ट जनादेश



ट्रंप अब एक जटिल राजनीतिक स्थिति का सामना कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वे याद रखें कि हर मतपत्र पर वही उम्मीदवार हैं। उन्हें इसे अपने ऊपर एक जनमत संग्रह कहलाना पसंद था। रिपब्लिकन ने भी यही रुख अपनाया। वहीं, डेमोक्रेट्स ने इसे ट्रम्प के जन-विरोधी कार्यक्रमों पर एक जनमत संग्रह के रूप में पेश किया।अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजे न केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा प्रशासन पर, बल्कि लैटिन अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देशों की राजनीतिक स्थिति पर भी बड़ा असर डालेंगे। वैश्विक स्तर पर, ट्रंप की यह बड़ी हार दुनिया के उन विभिन्न समूहों का हौसला बढ़ाएगी जो अलग-अलग तरह की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। वामपंथी राष्ट्रपति लूला की ऐतिहासिक जीत के महज दस दिन बाद अमेरिकी मतदाताओं का यह फैसला संकेत देता है कि इस महाद्वीप में एक नया राजनीतिक माहौल बन रहा है, जो अति दक्षिणपंथी उभार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। ताजा नतीजों के अनुसार, सीनेट में डेमोक्रेट्स को लगभग 55 सीटें मिली हैं, जबकि रिपब्लिकन को 45 सीटें मिली हैं; यानी डेमोक्रेट्स के पास स्पष्ट बहुमत है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) की 435 सीटों में से डेमोक्रेट्स को 240 से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है, जो बहुमत के लिए जरूरी 218 सीटों से कहीं ज्यादा है। इस तरह, कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण मिलने से डेमोक्रेट्स को ट्रंप पर अपनी नीतियां बदलने के लिए दबाव डालने का एक बड़ा मौका मिल गया है।अमेरिकी संविधान के अनुसार, ट्रंप के पास वीटो शक्तियां हैं। वे कांग्रेस की राय को नजरअंदाज करते हुए अपने कुछ कार्यक्रमों को लागू करने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। 3 नवंबर के चुनावों के बाद उनकी राजनीतिक हैसियत कमजोर हुई है। ऐसे में शायद वे कांग्रेस पर उस तरह से अपनी मर्जी नहीं थोप पाएंगे, जैसा कि उन्होंने 21 जनवरी, 2025 को पदभार संभालने के बाद पिछले दो वर्षों में किया है। अपने खिलाफ आए इस स्पष्ट फैसले के बाद ट्रंप के तेवर कुछ नरम पड़ गए हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे अपने कार्यकाल के बचे हुए दो वर्षों में कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करेंगे। उनके चुनाव प्रचार के दौरान का वह दावा अब गायब था कि डेमोक्रेट्स मतदान के आंकड़ों में हेरफेर कर सकते हैं। उन्होंने इस जनादेश को स्वीकार कर लिया है। समाचार पढ़ें

ट्रंप अब एक जटिल राजनीतिक स्थिति का सामना कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वे याद रखें कि हर मतपत्र पर वही उम्मीदवार हैं। उन्हें इसे अपने ऊपर एक जनमत संग्रह कहलाना पसंद था। रिपब्लिकन ने भी यही रुख अपनाया। वहीं, डेमोक्रेट्स ने इसे ट्रम्प के %जन-विरोधी% कार्यक्रमों पर एक जनमत संग्रह के रूप में पेश किया। अब इस करारी हार के बाद, वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, हालांकि उन्होंने चालाकी दिखाते हुए यह कहा कि अगर वे खुद उम्मीदवार होते, तो उन्हें भारी जीत मिलती।लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के नेता काफी नाराज और निराश हैं। उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को अपने ही गढ़ों में भारी हार का सामना करना पड़ा, खासकर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां ट्रम्प ने सबसे ज्यादा प्रचार किया था। पिछले 94 वर्षों में पहली बार, कंसास में एक डेमोक्रेट ने सीनेट की सीट जीती, जहां एडम हैमिल्टन ने रोजर मार्शल को हराया। ट्रम्प के लिए एक और बड़ी व्यक्तिगत हार मिशिगन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद की जीत रही। ट्रम्प ने हमेशा की तरह सैयद के खिलाफ इस्लाम-विरोधी बयानबाजी की, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें स्पष्ट बहुमत से चुन लिया। समाचार पढ़ें

रिपब्लिकन इस बात से हैरान हैं कि ट्रम्प द्वारा चुने गए ज्यादातर उम्मीदवार हार गए हैं। टेक्सास और साउथ कैरोलिना में, ट्रम्प ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया था। ये सभी पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन के गढ़ रहे हैं, और राष्ट्रपति के प्रचार और समर्थन के बाद, यह माना जा रहा था कि वे आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन 3 नवंबर के चुनावों में, वहां के रूढ़िवादी मतदाताओं ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया, जिससे रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा—जो राष्ट्रपति चुनावों में सीटों के लिए हमेशा टेक्सास पर निर्भर रहती है। रिपब्लिकन-बहुल राज्यों के ये रुझान 2028 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए एक चिंताजनक संकेत देते हैं।

ट्रम्प समर्थित उम्मीदवारों की विफलता के विपरीत, बर्नी सैंडर्स और उनके वामपंथी डेमोक्रेट्स ने 3 नवंबर के चुनावों में बड़ी सफलता हासिल की है। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन डीएसए सूत्रों का दावा है कि सैंडर्स द्वारा समर्थित 70 उम्मीदवारों में से 40 से अधिक जीत गए हैं। ये सभी सैंडर्स के उन कार्यक्रमों के समर्थक हैं, जो मजदूरों और गरीबों के लिए अधिक सुविधाओं, रक्षा खर्च में कटौती और ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की वकालत करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में डीएसए की बढ़ती संख्या को देखते हुए, पार्टी नेतृत्व पर अब भारी दबाव होगा कि वे कांग्रेस में अपने एजंडे को और अधिक %जन-हितैषी% दिशा में ले जाएं। लैटिन अमेरिका और यूरोप, दोनों ही जगहों पर वामपंथियों और उदारवादियों के बीच काफी उत्साह है, क्योंकि घोर दक्षिणपंथी विचारधारा के दो बड़े स्तंभ- डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के जायर बोल्सोनारो- हार गए हैं। लैटिन अमेरिका में %सत्ता परिवर्तन% के ट्रंप के एजंडे को, ब्राजील में लूला के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले ही एक बड़ा झटका लग चुका है। इसके अलावा, लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में अन्य घोर दक्षिणपंथी पार्टियों को मिलने वाला समर्थन भी फिलहाल कम हो सकता है। ट्रंप अब नवंबर 2028 तक अपनी सत्ता बचाए रखने की जद्दोजहद में ही इतने व्यस्त रहेंगे कि उनके लिए कुछ और कर पाना मुश्किल होगा, खासकर तब जब अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स फिर से मजबूत होकर लौट आए हैं।भारत की बात करें तो, ट्रंप की हार के नतीजों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर चिंतित होंगे। ट्रंप का %मगा% (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) एजेंडा, काफी हद तक नरेंद्र मोदी के अपने एजेंडे से मिलता-जुलता है। अमेरिका में मौजूद भाजपा से जुड़े संगठन, जिनमें वीएचपी और अन्य हिंदू संगठन शामिल हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हार गए। वे भी ट्रंप की तरह ही इस्लाम से नफरत रखते हैं।

डेमोक्रेटिक पार्टी के कई लोग नरेंद्र मोदी को ट्रंप जैसा ही मानते हैं। असल में, बर्नी सैंडर्स ने मोदी को उन दक्षिणपंथी नेताओं में से एक बताया है, जिनका नेतृत्व ट्रंप करते हैं। अब अमेरिकी संसद अर्थात कांग्रेस में सैंडर्स और भी ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि उनके गुट के कई सदस्य चुनकर आए हैं। अमेरिका के साथ भारत के हितों की रक्षा के लिए, वाशिंगटन में भारतीय दूतावास को डेमोक्रेट्स के साथ और ज्यादा बातचीत करनी होगी। भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर, आने वाले साल में मोदी सरकार को अमेरिकी कांग्रेस और उसकी कमेटियों की और ज्यादा आलोचना का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। समाचार पढ़ेंइस साल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से दो बार मुलाकात होगी। पहली मुलाकात इसी महीने के मध्य में मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान होगी। इसके बाद, दिसंबर के मध्य में, भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति से मियामी, फ्लोरिडा में जी-20 बैठक के दौरान मुलाकात होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी, ट्रंप की राजनीतिक रूप से कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं।

क्वींसटाउन

दुनिया की रोमांच राजधानी

उस शहर जाने की कल्पना ही रोमांचक हो सकती है जिसे दुनिया की एडवेंचर कैपिटल के रूप में शोहरत हासिल हो। जिन्हें हम एक्सट्रीम एडवेंचर की संज्ञा देते हैं, वे सभी यहां हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन शहर की। कहा जाता है कि उन्नीसवीं सदी के मध्य में जब क्वींसटाउन में शॉटओवर नदी में सोना मिलने की खबर फैली तो लोग यहां उमड़ने शुरू हो गए थे। आखिरकार जब सोना खत्म हो गया तो यहां पहुंचे लोगों का ध्यान यहां के पहाड़ों और नदियों की खूबसूरती पर गया और तब उन्होंने यही बसने का फैसला कर लिया। रोमांच में यहां शुरुआत पिछली सदी के मध्य में स्कीइंग से हुई।

1970 के दौरान जेट बोटिंग की शुरुआत हुई। यह एक तरह से विशुद्ध रूप से रोमांच की दुनिया को क्वींसटाउन की देन थी। शॉटओवर नदी की गहरी कंदराओं में से जेटबोट की राइड का रोमांच ही अलग है। कुछ ही समय बाद रिवर राफ्टिंग भी क्वींसटाउन की नदियों में शुरू हो गई। 1988 में ऐ जे हैकट ने यहां बंजी जंपिंग की शुरुआत की। क्वींसटाउन को बंजी जंपिंग का जनक माना जाता है। आज यहां बंजी जंपिंग की कई साइट हैं। एक समय तो हैकट एंड कंपनी 450 मीटर की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से बंजी जंपिंग करा रहे थे। हालांकि सरकारी नीतियां बदलने से बाद में उसे रोकना पड़ा।

क्वींसटाउन ही टेंडम पैरापेंटिंग व कमर्शियल स्काइडाइविंग का भी मुख्य अड्डा है। इसके अलावा यहां टेंडम हैंग ग्लाइडिंग, पैरासेलिंग व एब्सेलिंग जैसी गतिविधियां भी होती हैं। सैलानी क्वींसटाउन केवल एडवेंचर के लिए जाते हैं, जबकि वहां की प्राकृतिक खूबसूरती भी किसी जगह से कम नहीं।

कैसे जाएं: न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के दक्षिण-पश्चिमी कोने में स्थित क्वींसटाउन में हालांकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन यहां की सारी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें आस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों से होकर हैं।



खतलिंग

ग्लेशियर का नजारा

उत्तराखंड में एक वक्त 7,941 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बर्फ से ढका रहता था, जो यहाँ के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 15 प्रतिशत क्षेत्र है। यमुना, गंगा और काली नदी समेत उनकी कई सहस्त्रधाराएँ इसी क्षेत्र में जन्म लेती हैं, लेकिन यह क्षेत्र लगातार सिमट रहा है। यहाँ के तमाम ग्लेशियर पिघल रहे हैं।

चार धामों की यात्रा के अलावा साहसिक पर्यटन के प्रेमियों में खतलिंग ग्लेशियर के दर्शन को पाँचवाँ धाम दर्शन माना जाता है। यहीं से केदारनाथ तक पैदल यात्रा क्षेत्र भी है। पिछले हफ्ते इसी यात्रा मार्ग पर ट्रैकिंग के लिए कुछ पर्यटकों का दल भारी बर्फबारी में फँसने से राज्य में हड़कंप मच चुका है। बमुश्किल इस यात्री दल के तीन पर्यटकों को हेलिकॉप्टरों से निकाला गया तो छः अन्य लोगों को दो दिन बाद त्रियुगी नारायण क्षेत्र में आईटीबीपी एवं पुलिस की गठित टीमों ने पैदल रास्ते से जाकर ढूँढ निकाला।

यही है कस्तूरी मृगों का क्षेत्र :

पाँचवें धाम खतलिंग को जाने वाले मार्ग पर फँसे इन पर्यटकों ने वन विभाग से यहाँ जाने की अनुमति नहीं ली थी। इस क्षेत्र में कस्तूरी मृग क्षेत्र होने से यहाँ जाने की पूर्वानुमति आवश्यक है। 3,700 मीटर की ऊँचाई पर खतलिंग ग्लेशियर पहुँचने के रास्ते में चौकी बुग्याल रुद्रागंगा, हिमानी गुफा, दुमलिया ताल भी दर्शनीय हैं। यहाँ से सात किलोमीटर की दूरी तय कर गंगोत्री पहुँचा जा सकता है। यहाँ से साढ़े छः हजार मीटर की ऊँचाई पर स्थित सतलिंग तेज चमकता है।

स्फटिक लिंग जो ग्रेनाइट धातु से बना है, पर बर्फ नहीं टिकती और भगवान शिव का आत्मलिंग का खिताब इसे प्राप्त है । 6,460 मीटर जोगिन चोटी, मयाली टॉप के रास्ते वासुकीताल होते हुए 14 किलोमीटर दूरी तय कर केदारनाथ धाम पहुँचना संभव है । मयाली टॉप की चोटी से तिब्बत का इलाका दिखाई देता है।

पिघल रहे ग्लेशियर :

हिमालय में तैंतीस हजार वर्ग किलोमीटर में ग्लेशियर फैले हैं जो पूरे हिमालय क्षेत्र के 17 प्रतिशत रहे हैं। गोमुख, मिलम, पिंडारी, खतलिंग व नामिक जैसे उत्तराखंड के हजारों ग्लेशियर पानी की मीनारों का काम करते हैं। हजारों साल पहले गौमुख ग्लेशियर गंगोत्री से मिलता था, लेकिन आज गंगोत्री व गोमुख के बीच की दूरी 19 किलोमीटर है।

पिछले दो सौ वर्षों में गंगोत्री व गोमुख के बीच की दूरी ही नहीं बढ़ी। ग्लेशियर का स्नाउट भी खिसकता जा रहा है। मिलम ग्लेशियर 1828 में मिलम गाँव से दो किलोमीटर पर बताया गया जो अब छः किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है। खतलिंग ग्लेशियर का मुख जो चौकी ताल पर था, अब सात किलोमीटर दूर है। पिंडारी ग्लेशियर भी काफी पीछे चला गया।

बढ़ते लोग, बढ़ता ताप :

सन 1808 तक गंगोत्री क्षेत्र में गंगा की मूर्ति के पूजन की परंपरा थी, लेकिन यहाँ दस-पंद्रह लोग ही रहते थे। गंगा की मूर्ति के साथ ये लोग भी अपने गाँवों में वापस चले जाते थे। 1981 की जनगणना में गंगोत्री की स्थाई आबादी लगभग 125 के आसपास थी जो आज हजारों तक पहुँच चुकी है। साधु-संन्यासी ही काफी पहले पहुँचे थे। चार धामों में से बद्रीनाथ में ही यह संख्या श्रद्धालुओं के हिसाब से लाख तक पहुँचती थी। अब यहाँ एक हफ्ते में लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं।

पूर्ण कुंभकाल के वक्त ही बद्रीनाथ से ज्यादा श्रद्धालु आते थे। 1808 के पूर्ण कुंभ में 45 हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुँचे थे, जबकि 2010 के पूर्ण कुंभ के बाद दो दिन में यह संख्या पार कर ली गई। 1808 में केदारनाथ की यात्रा विषम थी। उस साल केदारनाथ गए कई यात्री मारे भी गए थे। अब तमाम साधन, बढ़ते गाड़ियों व रेल नेटवर्क बढ़ने से तीर्थयात्रियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। इसी तरह इस क्षेत्र के ग्लेशियरों में भी ट्रैक कर जाने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

प्रकृति छेड़छाड़ ने पैदा किया संकट :

इसी तीर्थ क्षेत्र के आसपास बुग्यालों, ग्लेशियरों एवं तमाम खूबसूरत घाटियों व नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ से भी यहाँ के माहौल में बदलाव आया है। स्वयं चिपको नेता चंडीप्रसाद भट्ट ने भी इस तरह की गतिविधियों को विश्व धरोहर पार्कों के आसपास हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर भ्यूंडार घाटी जल विद्युत परियोजना समेत तमाम क्षेत्रों की परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध बताया है।

इस बाबत उन्होंने केंद्र को पत्र भी भेजकर इस संवेदनशील क्षेत्र में इस गतिविधि को लगाम लगाने की माँग की है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी से सात किलोमीटर की दूरी पर भ्यूंडार घाटी जल विद्युत परियोजना भी इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जारी है। इस आदेश के अनुसार विश्व धरोहर से 10 किलोमीटर की परिधि में इस तरह की परियोजनाएँ प्रतिबंधित हैं। तथापि यहाँ इस तरह की परियोजनाओं का बेरोकटोक निर्माण इस क्षेत्र में प्रकृति प्रेमियों के रोष का कारण बन रहा है।



कला-शिल्प का अद्भुत संगम

खजुराहो

खजुराहो के मंदिर भारतीय कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इन मंदिरों की दीवारों पर उकरी देवी-देवताओं की विभिन्न मुद्राओं की मनोहारी प्रतिमा अपने आप में दुर्लभ है, जिसके समान कोई ओर नहीं है। मध्यप्रदेश में स्थित खजुराहो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है।

हर साल लाखों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक खजुराहों आते हैं व यहाँ की खूबसूरती को अपनी स्मृति में कैद करके ले जाते हैं। यहाँ शाम के वक्त होने वाले लाइट शो में खजुराहो के मंदिरों की खूबसूरती का चरम देखने को मिलता है, जो एक यादगार व अविस्मरणीय अनुभव होता है।

भारतीय कला व संस्कृति के संगम स्थल खजुराहों के आसपास भी कई ऐसे स्थान है, जो आपकी खजुराहो यात्रा को पूर्णता प्रदान करते हैं। इनमें खजुराहो से 25 किमी दूर स्थित राजगढ़ पैलेस (हैरिटेज होटल), रंगून झील (पिकनिक स्पॉट), पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आदि स्थल है। खजुराहो को प्यार का प्रतीक भी कहा जाता है। यहाँ काम मुद्रा में मग्न देवताओं की भी मूर्तियाँ है, जो अश्लीलता नहीं बल्कि सौंदर्य और प्यार की प्रतीक हैं। प्यार के साक्षी इन्हीं मंदिरों में प्रतिवर्ष कई जोड़े परिणय सूत्र में बँधकर अपने दांपत्य जीवन की शुरुआत करते हैं।

खजुराहो एक पर्यटक स्थल होने के साथ-साथ मंदिरों के गाँव के रूप में भी विख्यात है। यहाँ के मंदिर लगभग 1000 सालों से भी अधिक पुराने हैं, जिन्हें मध्यभारत के चंदेल राजपूत राजाओं ने बनवाया था।

वर्तमान में प्राचीन 85 मंदिरों में से मात्र 22 मंदिर ही सुरक्षित बचे हैं। शेष मंदिर आज खंडहर के रूप में तब्दील होकर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी आदि तीन भागों में विभाजित हैं।



पश्चिमी भाग के मंदिर :- खजुराहो में पश्चिमी भाग के मंदिरों में प्रमुख मंदिर कंडरिया महादेव मंदिर, चौंसठ योगिनी मंदिर (ग्रेनाइट से बना सुंदर मंदिर), काली माँ का मंदिर, देवी जगदंबा मंदिर आदि प्रमुख हैं। इन मंदिरों के उत्तर में चित्रगुप्त मंदिर (सूर्य देवता का मंदिर), विश्वनाथन मंदिर (तीन मुखी ब्रह्मा की प्रतिमा तथा 6 फीट ऊँची नंदी प्रतिमा), मटंगेश्वर मंदिर (8 फीट ऊँचा शिवलिंग) आदि स्थित है।

मंदिरों में स्थित प्रतिमाओं की जर्जर स्थिति को देखते हुए इनमें से कई मंदिरों में पूजा करना प्रतिबंधित है। इनमें से केवल ममटंगेश्वर मंदिर में ही अब तक पूजा करना जारी है।

पूर्वी भाग के मंदिर :

इस भाग में हिंदू व जैन दोनों के देवी-देवताओं की दुर्लभ प्रतिमाएँ स्थित हैं। मंदिरों का यह भाग खजुराहो गाँव के समीप स्थित है। पूर्वी भाग का सबसे बड़ा मंदिर जैन तीर्थंकर 'भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर' है। इसके बाद दूसरा जैन मंदिर 'घाटी मंदिर' है। इस मंदिर के उत्तर में 'आदिनाथ मंदिर' हैं। मंदिरों के इस समूह में ब्रह्मा, वामन आदि हिंदू देवताओं के मंदिर भी शोभायमान है।

दक्षिणी भाग के मंदिर :

मंदिरों का यह समूह खजुराहो गाँव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनमें सबसे अच्छा मंदिर 'चित्रभुज मंदिर' है। इस भाग के मंदिरों से कुछ दूरी पर सड़क के उस पार जैन मंदिरों का एक समूह है, जिनमें कई जैन तीर्थंकरों के सुंदर व आकर्षक मंदिर है।

खजुराहो के आसपास: भारतीय कला व संस्कृति के संगम स्थल खजुराहों के आसपास भी कई ऐसे स्थान है, जो आपकी खजुराहो यात्रा को पूर्णता प्रदान करते हैं। इनमें खजुराहो से 25 किमी दूर स्थित राजगढ़ पैलेस (हैरिटेज होटल), रंगून झील (पिकनिक स्पॉट), पन्ना राष्ट्रीय उद्यान (34 किमी दूर) आदि रमणीय स्थल हैं।

भारत की इस विरासत को देखना मात्र ही अपने आप में भारतीय कला से रूबरू होना है, जो अपने आप में अनूठी है, प्राचीन है व गौरवशाली है। आप भी मंदिरों के इस गाँव की सुंदरता को निहारने एक बार अवश्य खजुराहों जाएँ।

हिन्दी दैनिक प्रातःकाल एक्सप्रेसः- स्वामी, प्रकाशक, फिरदौस फातिमा द्वारा एफ-1, अनमोल होम, प्लाट नं0 53, गोविन्द गार्डेन, राइसेन रोड़, भोपाल मध्य प्रदेश-462023 से प्रकाशित एवं अशोक कुमार खुराना, द्वारा पी.जी. इंफ्रास्ट्रचर एण्ड सर्विस प्रा.लि. करोंद भानपुर बाइपास रोड़ भोपाल मध्य प्रदेश-462037 से मुद्रक। पंजीयन संख्या : MPHIN/26/A1603, संपादकः परवेज आलम,मो0 9336781957, पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार। इससे उत्पन्न समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय भोपाल होगा।



सलमान खान ने बताई 'मातृभूमि' की को-स्टार

चित्रांगदा सिंह

की सबसे बड़ी खूबी, बोले- वो इनसिक्योर नहीं हैं

सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. सलमान की इस फिल्म का फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में सलमान के साथ पहली बार एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. बीते दिन मुंबई में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था. इस इवेंट में सलमान से उनकी को-एक्टर चित्रांगदा की खूबियों को लेकर सवाल किया गया था, जिसका जवाब भाईजान ने पूरी सच्चाई के साथ दिया है.दरअसल, इवेंट के दौरान पत्रकार ने चित्रांगदा सिंह की खूबियों के बारे में सलमान से सवाल किया था. इसके जवाब में एक्टर ने चित्रांगदा की तारीफ करते हुए कहा कि वह काफी आत्मविश्वासी हैं और अपने मन में किसी तरह की असुरक्षा की भावना नहीं रखती हैं.

पहली साथ नजर आएंगे सलमान और चित्रांगदा

सलमान खान और चित्रांगदा सिंह फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के जरिए पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं. यह फिल्म साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और



चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है. इसकी कहानी शिव अरोर की किताब 'इंडियाज मोस्ट फियरलेस' में दिए गए घटनाक्रम से प्रेरित है. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है, इसमें सलमान भारतीय सेना के कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं.

उन्होंने इस टकराव के दौरान 16 बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व किया था. उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था. फिल्म में सलमान और चित्रांगदा के अलावा मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, जेन शॉ और अभिलाष चौधरी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

'बैटल ऑफ गलवान' से बदला गया फिल्म का नाम

इस फिल्म की घोषणा पहले 'बैटल ऑफ गलवान' नाम से की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' कर दिया गया. सलमान ने बताया था कि फिल्म की रिलीज में देरी की वजह बड़े स्तर पर किए जा रहे VFX का काम है. मेकर्स फिल्म के विजुअल्स को बेहतर बनाने के लिए उन पर काम कर रहे हैं. इसके अलावा चित्रांगदा सिंह को लगी चोट के बाद प्रोडक्शन को दोबारा पटरी पर लाने में भी समय लगा. सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

लहंगा-चोली पहनकर महिला बने काजी तौकीर, मनीष गोयल पर लगाया 'गलत तरीके से छूने' का आरोप!



भारतीय टेलीविजन के सबसे धमाकेदार और विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में हर दिन नया हंगामा और ट्विस्ट देखने को मिल रहा है. हाल ही में घर के अंदर हंसी-मजाक और मस्ती का एक ऐसा पल आया, जिसने चंद मिनटों में ही विवाद का रूप ले लिया. सिंगर और कंटेस्टेंट काजी तौकीर ने घर में महिला का रूप धारण कर घरवालों का मनोरंजन करने की कोशिश की, लेकिन एक्टर मनीष गोयल संग हुई मस्ती के बाद ये मामला द्वकाजरूम कांड और 'गलत तरीके से छूने' के गंभीर आरोपों तक पहुंच गया. शो का नया प्रोमो सामने आते ही दर्शकों के बीच खलबली मच गई है.'बिग बॉस 20' के नए प्रोमो में काजी तौकीर का एक बेहद अनोखा और अलग अंदाज़ देखने को मिला. काजी ने घर में महिला का गेटअप लिया, लहंगा-चोली पहना और सिर पर लाल दुपट्टा ओढ़कर एंट्री मारी. उनका ये अवतार देखकर घर के तमाम सदस्य अपनी हंसी नहीं रोक पाए. घरवालों ने ज़ोरदार हूटिंग करके उनका उत्साह बढ़ाया. टीवी एक्ट्रेस माही विज ने तो काजी को 'हीरोइन' का टैग तक दे दिया. काजी भी अपने इस फीमेल गेटअप को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए अदाएं दिखाते और घरवालों को छेड़ते हुए नजर आए.

बांहों में उठाकर किया डांस, फिर वॉशरूम में खींचकर किया लॉक

काजी की इस मस्ती के बीच एक्टर मनीष गोयल भी उनके साथ ताल से ताल मिलाने लगे. जब काजी ने मस्ती में मनीष को छेड़ा, तो मनीष ने भी मजाकिया अंदाज़ में जवाब दिया. इसके बाद मनीष गोयल ने काजी को अपनी बाहों में उठा लिया और उनके साथ रोमांटिक अंदाज़ में डांस करने लगे. घर के अन्य सदस्य दोनों की ये बॉन्डिंग देखकर काफी हंस रहे थे. लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब मनीष गोयल काजी को खींचकर वॉशरूम के अंदर ले जाने की कोशिश की. शुरुआत में घरवालों और दर्शकों को लगा कि ये सब हंसी-मजाक का ही एक हिस्सा है, लेकिन बाद में काजी तौकीर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

काजी पर फूटा मनीष का गुस्सा

लिविंग एरिया में सबके सामने काजी तौकीर ने मनीष गोयल पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी जताई. काजी ने कहा, मनीष भाई, सबकी नजर आज आपके ऊपर थी, जो आपने हरकत की मेरे साथ. वॉशरूम क्यों लेकर जा रहे थे मुझे? इस पर मनीष ने पूछा क्या मैं लेकर गया तो काजी ने कहा, अगर मैं नहीं रोकता न तो लेकर जाते वॉशरूम. फिर काजी माही विज से कहते हैं वो कैसा झपटे मुझपे. काजी ने मनीष से कहा कि मैंने मुंह से मस्ती की और आपने हाथों से.

'बिग बॉस' विनर के घर नारकोटिक्स की रेड, भड़के एक्टर, CM विजय से पूछा ये सवाल



तमिल टेलीविजन का लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस तमिल' कंटेस्टेंट्स को रातों-रात घर-घर में पहचान दिला देता है. 'बिग बॉस सीजन 4' में रनर-अप रहे और 2022 में आए 'बिग बॉस अल्टिमेट सीजन 1' (ओटीटी) के विनर बालाजी मुरुगादास एक बार फिर जबरदस्त सुर्खियों में हैं. हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग और पुलिस की टीम ने बालाजी मुरुगादास के घर पर अचानक पहुंचकर तलाशी ली. अपने घर हुई इस कार्रवाई के बाद भड़के अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर पुलिस प्रशासन से तीखे सवाल पूछे हैं. उनका पोस्ट अब वायरल हो रहा है.तमिल छोटे पर्दे पर 'बिग बॉस' का क्रेज ऐसा है कि इसमें हिस्सा लेने वाले कांटेस्टेंट तमिलनाडु की जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हो जाते हैं. यहां तक कि शो न देखने वाले लोग भी इन्हें 'बिग बॉस फेम' के रूप में पहचान लेते हैं. इसी लोकप्रियता के चलते बड़े पर्दे के कलाकार भी इस शो में आने के लिए उत्सुक रहते हैं. बालाजी मुरुगादास ने 'बिग बॉस तमिल 4' में अपनी छाप छोड़ी थी, जिसके बाद उन्हें तमिल सिनेमा में काम करने के अवसर मिले. इन दिनों वो टीवी पर चल रहे कुकिंग रियलिटी शो 'मास्टरशेफ तमिल में एक प्रतियोगी के रूप में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.

घर पहुंची 15 पुलिसकर्मियों की टीम

इसी बीच बालाजी मुरुगादास के घर पर नारकोटिक्स विभाग की टीम द्वारा तलाशी लिए जाने की खबर सामने आई. इस पूरी घटना के बाद बालाजी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी. अपने वायरल पोस्ट में बालाजी मुरुगादास ने लिखा, मैं ये जानना चाहता हूं कि शिकायत किसने दर्ज कराई है. CM विजय, मुझे ये जानने का पूरा हक है कि शिकायत किसने की और किस वजह से की. बार-बार पूछने के बावजूद अधिकारियों ने मुझे ये जानकारी नहीं दी. मैं अपना ब्लड टेस्ट (रक्त जांच) कराने के लिए भी पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन मुझे आपकी पुलिस प्रणाली पर शर्म आती है.आगे अपनी बात रखते हुए अभिनेता ने बताया, मेरे घर पर 15 पुलिसकर्मी आए थे, लेकिन वहां छानबीन के दौरान उन्हें सिर्फ 3 बिल्लियां और 1 कुत्ता ही मिला. मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर किस आधार पर वो मेरे घर आए थे. उनके पास कोई सर्च वारंट भी नहीं था. चूंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, इसलिए मैंने खुद उन्हें घर के अंदर आने की अनुमति दी, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई पर मुझे स्पष्टीकरण और जवाब चाहिए.

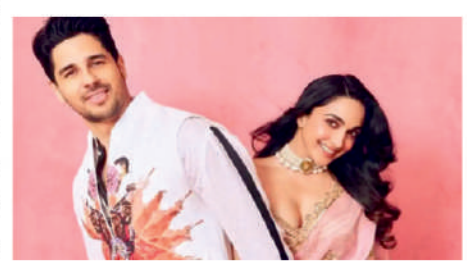


टॉक्सिक के बाद लंबा ब्रेक ले रही हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस

कियारा आडवाणी

सामने आई वजह

बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कियारा आडवाणी को अब अच्छा-खासा समय हो गया है. वे कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहीं और साल 2026 में तो वे यश के अपोजिट टॉक्सिक फिल्म में नजर आई थीं. लेकिन ये बड़े बजट की फिल्म थिएटर्स में नकार दी गई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर सकी. अब कियारा आडवाणी ने फिल्मों से लंबा ब्रेक लेने का प्लान बना लिया है. लेकिन इसकी वजह उनका फिल्मी करियर नहीं है बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है.एक्ट्रेस ने अक्टूबर 2026 में ही फैंस के सामने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर ली थी. अब एक्ट्रेस एक बार फिर से मां बनने की तैयारी में हैं. इसलिए वे एक पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी चाहती हैं. इसके लिए वे फिल्मों से दूरी बनाने की योजना बना रही हैं.



लंबे वक्त तक फिल्मों से दूर रहेंगी कियारा ?

कियारा आडवाणी ने शादी के बाद से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है. अब अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी के वक्त भी वे इस बैलेंस को मेंटेन रखना चाहती हैं. सिर्फ कियारा ही नहीं रिपोर्ट्स तो ये भी है कि खुद सिद्धार्थ मल्होत्रा भी कुछ समय तक फिल्मों से दूरी बनाने जा रहे हैं. वे अपनी फैमिली को प्रॉयोरिटी देना चाहते हैं. सिद्धार्थ इस प्रेग्नेंसी फेज में कियारा का साथ देना चाहते हैं और उनका खयाल रखना चाहते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2027 में सिद्धार्थ मल्होत्रा भी वर्क कमिट्मेंट्स से दूरी बनाकर रखने वाले हैं.

दूसरी संतान का स्वागत करेंगे कियारा-सिद्धार्थ

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 7 फरवरी 2023 को शादी की थी. कपल की ये ग्रैंड वेडिंग चर्चा में रही थी. इसके बाद दोनों ने जुलाई 2025 को बेबी गर्ल का स्वागत किया था. वहीं अब वे दूसरी संतान के भी स्वागत की तैयारी में हैं. फिलहाल कियारा आडवाणी के पास कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट नहीं हैं. वहीं 2026 में सिद्धार्थ की भी फिल्म द वन सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. ये फिल्म भी फैंस को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर सकी थी. इसमें उनके अपोजिट तमन्ना भाटिया नजर आई थीं.

KL राहुल ने जीता दिल

अवॉर्ड में मिला महंगा फोन मैच अधिकारी को किया गिफ्ट



फोन मिलने पर हैरान रह गई महिला अधिकारी

बीसीसीआई ने राहुल के इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में महिला अधिकारी फोन मिलने के बाद अपनी खुशी और हैरानी जाहिर करती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि राहुल ने उन्हें अपना फोन दे दिया और वह इस तरह के तोहफे की बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही थीं। उन्होंने इस gesture के लिए भारतीय बल्लेबाज का आभार भी जताया।

वेलिंगटन, एजेंसी। भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार बल्लेबाजी के बाद मैदान के बाहर भी ऐसा काम किया, जिसने फैंस का दिल जीत लिया। भारत की 4 रन से रोमांचक जीत के बाद राहुल को 'गेमचेंजर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला था। लेकिन उन्होंने इनाम में मिले महंगे स्मार्टफोन को अपने पास रखने के बजाय स्टेडियम की एक महिला अधिकारी को गिफ्ट कर दिया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पेरिस मास्टर्स

अल्काराज ने रूड को हराकर फाइनल में बनाई जगह



सातवें अलग मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे

कैस्पर रूड के खिलाफ जीत के साथ ही अल्काराज सात अलग-अलग एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एटीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, 23 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी अब तक मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में कुल 11 चैंपियनशिप मुकाबले खेल चुके हैं।

पेरिस, एजेंसी। कार्लोस अल्काराज ने पेरिस मास्टर्स के सेमीफाइनल में कैस्पर रूड को 6-4, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब उनका सामना बेन शेल्टन से होगा। शेल्टन ने हाल ही में यूएस ओपन में अल्काराज को हराया था। दोनों के बीच अब तक हुए चार मुकाबलों में स्पेनिश खिलाड़ी ने तीन जीत दर्ज की हैं। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पेरिस मास्टर्स के फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया।

एलेना ने 2026 डब्ल्यूटीए फाइनल्स से नाम वापस लिया



नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया की नंबर 1 एलेना रायबाकिना ने वायरल बीमारी के कारण इंडियन वेल्स में होने वाले 2026 डब्ल्यूटीए फाइनल्स से नाम वापस ले लिया है। रायबाकिना ने कहा, 'मुझे अपने सभी फैंस और समर्थकों को यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बदकिस्मती से मुझे इस साल डब्ल्यूटीए फाइनल्स से नाम वापस लेना पड़ रहा है।' उन्होंने कहा, 'मेरा सीजन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मेरा शरीर अभी मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। मैं घर पर आराम करने और ठीक होने में कुछ समय बिताऊंगी और 2027 सीजन के लिए खुद को तैयार करूंगी। डब्ल्यूटीए फाइनल्स एक बहुत ही खास टूर्नामेंट है और मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूं। मार्च में इंडियन वेल्स में वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती।'

डब्ल्यूटीए की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्टा कोस्त्युक ग्रुप 1 में रायबाकिना की जगह लेंगी, और रविवार को टूर्नामेंट के पहले मैच में लिंडा नोस्कोवा का सामना करेंगी। इसके अलावा, कोको गॉफ और जेसिका पेगुला भी बाद के राउंड रॉबिन मैचों में उनका सामना करेंगी। रायबाकिना ने साल के आखिर में होने वाले इस इवेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर एंट्री की थी, और सऊदी अरब के रियाद में 2025 एडिशन में आखिरी क्वालीफायर के तौर पर बिना हारे रहीं। इस सीजन में, वह यूएस ओपन में अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद पहली सिंगल्स क्वालिफायर थीं, जहां उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल की थी। रायबाकिना डब्ल्यूटीए पर अपना 2026 सीजन 54-14 के रिकॉर्ड और चार खिताब – ऑस्ट्रेलियन ओपन, स्टटगार्ट, यूएस ओपन और निंगबो के साथ खत्म करेंगी। नाम वापस लेने के बावजूद, उन्होंने टोक्यो में पीआईएफ द्वारा पेश की गई डब्ल्यूटीए साल के आखिर की नंबर 1 सिंगल्स रैंकिंग हासिल की। वर्ल्ड नंबर 1 और डिफेंडिंग चैंपियन के हटने के बाद, कोस्त्युक पहले अल्टरनेट के तौर पर कॉम्पिटिशन में उतरीं।

दीपक चाहर कप्तान, मानव सुतार उपकप्तान, अभिषेक-कार्तिक भी टीम में; सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए राजस्थान का स्क्वाड





नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के प्रतिष्ठित घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए लगातार अब टीमों के स्क्वाड जारी होने का सिलसिला जारी है। 32 टीमों वाला एलीट राउंड का यह टूर्नामेंट 14 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसी बीच रविवार रात एलीट ग्रुप ए में शामिल राजस्थान ने अपने स्क्वाड का ऐलान हुआ है। इस टीम की कप्तानी दीपक चाहर को सौंपी गई है, वहीं मानव सुतार उपकप्तान बनाए गए हैं। दीपक चाहर के भाई राहुल चाहर भी इस टीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को भी स्क्वाड में जगह मिली है। बाएं हाथ के 18 वर्षीय बल्लेबाज और दाएं हाथ के गेंदबाज अभिषेक मूंद को भी राजस्थान के स्क्वाड में शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी महिपाल लोमरोर भी स्क्वाड का हिस्सा हैं।

मुकुल की एंट्री, खलील अहमद बाहर – लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शानदार खेल दिखाकर आईपीएल 2026 में सुर्खियां बटोरने वाले मुकुल चौधरी को भी इस टीम में जगह मिली है। कार्तिक, मुकुल के अलावा तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज कुणाल सिंह राठौर का भी चयन हुआ है। हैमस्ट्रिंग इंजरी से रिकवर हो रहे खलील अहमद का इस टीम में चयन नहीं हो पाया है।

हैमिल्टन वनडे में कप्तान शुभमन गिल करेंगे फेरबदल



नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला सुबह 7.30 बजे शुरू होगा. भारतीय टीम शुरुआती दोनों मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बना चुकी है. अब इस मुकाबले को जीतकर वो सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में कम से कम एक बदलाव कर सकती है. अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका मिलने की उम्मीद है.

पाक-श्रीलंका

एक साथ इन 4 धुरंधरों का हुआ डेब्यू, मिली प्लेइंग इलेवन में एंट्री



नई दिल्ली, एजेंसी। श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तान की टीम बिल्कुल नए अंदाज में मैदान पर उतरी है. पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए अपनी प्लेइंग इलेवन में एक साथ चार नए खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका दिया है. अचानक हुए इन बदलावों और युवा खिलाड़ियों को तरजीह दिए जाने से क्रिकेट गलियारों में हलचल मच गई है.

श्रीलंका के खिलाफ मजबूत इरादों के साथ उतरी पाकिस्तानी टीम

रावलपिंडी में खेले जा रहे इस मुकाबले में सीनियर खिलाड़ियों के साथ इन युवा चेहरों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य टीम में नया जोश भरना है. पाकिस्तानी टीम की कमान बाबर आजम के हाथों में है, जबकि साउद शकील और सलमान अली आगा जैसे अनुभवी बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर को संभाल रहे हैं. गेंदबाजी आक्रमण में अनुभवी मोहम्मद अब्बास के साथ-साथ रजाउल्लाह और नए गेंदबाज साकिब खान मोर्चा संभाल रहे हैं. दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम भी कुसल मेंडिस और दिनेश चांदीमल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ बेहद मजबूत प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी है.

शतरंज

मध्य प्रदेश के अनुज श्रीवास्तव बने भारत के 100वें ग्रैंडमास्टर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत को शतरंज में अपना 100वां ग्रैंडमास्टर मिल गया है। मध्य प्रदेश के इंटरनेशनल मास्टर अनुज श्रीवास्तव ने रविवार को फिलीपींस में आयोजित 7वीं आसियान प्लस व्यक्तिगत ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीतकर यह उपलब्धि हासिल की। 22 वर्षीय अनुज भारत के 100वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। भारत को शतरंज में अपना 100वां ग्रैंडमास्टर मिल गया है। मध्य प्रदेश के इंटरनेशनल मास्टर अनुज श्रीवास्तव ने रविवार को फिलीपींस में आयोजित 7वीं आसियान प्लस व्यक्तिगत ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीतकर यह उपलब्धि हासिल की। 22 वर्षीय अनुज भारत के 100वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। फिलीपींस के मिसामिस ऑक्सिडेंटल स्थित असेंसो ग्लोबल यूथ लीडरशिप एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस टूर्नामेंट में अनुज ने कुल आठ में से सात अंक हासिल किए। उन्होंने प्रतियोगिता का पहला मुकाबला गंवाने के बाद शानदार वापसी की और खिताब अपने नाम किया।



विश्वनाथन आनंद थे भारत के पहले ग्रैंडमास्टर – भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद देश के पहले ग्रैंडमास्टर बने थे। उन्होंने 1987 में अपना तीसरा ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल किया था और 1988 में आधिकारिक तौर पर यह खिताब अपने नाम किया था। अनुज श्रीवास्तव के ग्रैंडमास्टर बनने के साथ ही भारत ने शतरंज में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है।

पांच महीने में मिले पांच नए ग्रैंडमास्टर – भारत ने जुलाई 2026 से नवंबर 2026 के बीच महज पांच महीनों में अपने 96वें से 100वें ग्रैंडमास्टर तक का सफर पूरा किया। अनुज श्रीवास्तव से पहले एथन वाज, हर्षवर्धन जीबी, एस अश्वथ और वी रथनेवेल को ग्रैंडमास्टर का खिताब मिला था।

कोच भी डरते हैं...



विराट कोहली को सुझाव देना हो सकता है खतरनाक

नई दिल्ली, एजेंसी। विराट कोहली को लेकर टीम इंडिया के पूर्व असिस्टेंट कोच रायन टेन डेस्काथे ने एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कोहली की बल्लेबाजी में एक तकनीकी खामी को दूर करने के लिए उन्हें काफी सावधानी बरतनी पड़ी? रायन टेन डेस्काथे ने ये किस्सा टॉकस्पोर्ट क्रिकेट पॉडकास्ट में बताया. उनके मुताबिक कोहली उस दौरे पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर ड्राइव करने की कोशिश में बार-बार आउट हो रहे थे. इस तरह से उनका लगातार आउट होना चर्चा का विषय बन गया था, और सवाल उठ रहे थे कि क्या कोचिंग स्टाफ इस मुद्दे पर काम कर रहा है या नहीं?

कोच के लिए ये हो सकता है खतरनाक

हालांकि, डेस्काथे ने माना कि कोहली जैसे कद के खिलाड़ी के साथ ऐसी बातचीत शुरू करना एक नाजुक काम हो सकता है. उनके अनुसार, कोचों को न केवल यह सोचना चाहिए कि वे क्या कहना चाहते हैं, बल्कि यह भी कि वे संदेश कैसे और कब देते हैं? डेस्काथे ने आगे कहा कि उनका मानना है कि एक कोच के लिए विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के पास जाना और हस्तक्षेप करना, और लगभग उन्हें ये बताना कि क्या हो रहा है, आपके लिए एक कोच के तौर पर खतरनाक हो सकता है. इसके लिए शब्दों का सही चुनाव और संदेश देने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है.

'विराट को सलाह देने से कोच भी डरते हैं'

रायन टेन डेस्काथे ने पॉडकास्ट में बताया कि विराट कोहली जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर को तकनीकी सुझाव देना आसान नहीं होता है. इतने बड़े कद वाले खिलाड़ी को तकनीकी सलाह देने से कोच भी डरते हैं. रायन टेन डेस्काथे नेबताया कि मैं कभी ऐसा कोच नहीं बनना चाहता जो सही बात कहने के लिए किसी और की राय से डरे. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चौथे टेस्ट में, मैं उनसे बात करने गया. बड़ी बात ये है कि वास्तव में विराट भी यही चाहते थे कि कोई उनसे उस खामी पर बात करे.

'दुनिया हिला देंगे...'

अक्षर पटेल ने अर्शदीप सिंह को चिढ़ाया

● ऋतुराज गायकवाड़ के सामने खुद भी घिरे



नई दिल्ली, एजेंसी। न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में रविवार (9 नवंबर) को बारिश ने भारतीय टीम का अभ्यास सत्र रोक दिया, लेकिन खिलाड़ियों की मस्ती जारी रही. इस दौरान अक्षर पटेल ने साथी गेंदबाज अर्शदीप सिंह को (इंडियन प्रीमियर लीग) 2027 से पहले ट्रेड की अफवाहों को लेकर जमकर चिढ़ाया. अक्षर ने मुंबई इंडियंस का मशहूर स्लोगन 'दुनिया हिला देंगे' कहकर अर्शदीप की खिंचाई की. दरअसल, अर्शदीप सिंह को लेकर चर्चा है कि वह पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियं में जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों फ्रेंचाइजी के बीच हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह की अदला-बदली पर बातचीत पूरी हो चुकी है. इस संभावित सौदे पर खिलाड़ियों की सहमति और ढुक्क अधिकारियों की मंजूरी बाकी है. अर्शदीप सिंह के बाद खिलाड़ियों ने अक्षर पटेल की भी खिंचाई की. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर को चेन्नई सुपर किंग्स से जोड़ने वाली अटकलों पर मजाक किया गया.

दिल्ली में प्रदूषण का कहर: अक्षरधाम में एक्यूआई 840 के पार, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी

नई दिल्ली, एजेंसी।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दीपावली के बाद कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। अक्षरधाम में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) करीब 840 दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहरीली हवा को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। लोगों ने बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।

प्रदूषण को लेकर शाहदरा निवासी एक युवक ने कहा कि दीपावली भारत का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार है। यह भगवान श्रीराम के वनवास से लौटने की खुशी में मनाया जाता है लेकिन लोगों को त्योहार मनाते समय दूसरों की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अस्थमा के मरीजों और छोटे बच्चों के फेफड़ों पर प्रदूषण का अधिक असर पड़ सकता है।

युवक ने दावा किया कि दीपावली की रात दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था। उन्होंने बताया कि समाचारों में द्वारका के कुछ इलाकों में एक्यूआई 2700 के पार पहुंचने की जानकारी देखी थी। वहीं, शाहदरा, नई दिल्ली, चांदनी चौक और लक्ष्मी नगर जैसे क्षेत्रों में भी एक्यूआई 1500 से 1700 के बीच होने का दावा किया। हालांकि, इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

एक अन्य स्थानीय युवक ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। दीपावली की शाम से ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी थी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को लेकर चेतावनी और सावधानियां जारी होने के बावजूद लोगों ने लापरवाही बरती और आतिशबाजी के जरिए प्रदूषण बढ़ाया।

वहीं, जयपुर से आए एक बुजुर्ग ने दिल्ली की हवा को बेहद खराब बताया। उन्होंने कहा कि जयपुर की तुलना में दिल्ली में प्रदूषण काफी अधिक महसूस हो रहा है। आसमान में धुंध छाई हुई है और सूरज भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने पंजाब सहित अन्य राज्यों में पराली जलाने को भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की एक बड़ी वजह बताया।

दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने एक बार फिर स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार के साथ-साथ आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी समझनी होगी।



दिवाली पर दिल्ली में आग संबंधी सूचनाओं में गिरावट, कोई बड़ी घटना नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली अग्निशमन सेवा को इस साल दिवाली के दौरान आग संबंधी 257 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें पिछले साल की तुलना में 4.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। राजधानी में पिछले साल आग संबंधी 269 सूचनाएं दर्ज की गई थीं। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस साल आग की किसी बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली और प्राप्त सभी सूचनाएं मामूली या मध्यम स्तर की आग की घटनाओं से संबंधित थीं। अधिकारी ने बताया कि विभाग को 2025 की तुलना में इस साल 12 कम सूचनाएं प्राप्त हुईं। दिवाली से पहले, दिल्ली अग्निशमन सेवा ने भीड़भाड़ वाले रिहायशी इलाकों और व्यस्त बाजारों सहित संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त अग्निशमन कर्मियों और वाहनों को तैनात करके अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था को मजबूत किया था। त्वरित प्रतिक्रिया दलों को ऐसे स्थानों पर तैनात किया गया था जो आग लगने के लिहाज से संवेदनशील हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि दमकल वाहन बिना किसी देरी के घटना स्थल तक पहुंच सकें। अधिकारियों के मुताबिक, विभाग ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने नियंत्रण कक्ष और आपातकालीन प्रतिक्रिया नेटवर्क को भी अलर्ट पर रखा था।

दीपावली पर झुलसने के 42 मामले एम्स में आए, पांच मरीजों की सर्जरी हुई

नई दिल्ली (एजेंसी)। दीपावली के दौरान पटाखों और अन्य कारणों से झुलसने के कुल 42 मामले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में आए। इनमें 11 मरीज गंभीर रूप से झुलसे हैं, जबकि 31 को मामूली चोटें आई हैं। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों में चार आईसीयू और सात वार्ड में भर्ती हैं। अब तक पांच मरीजों की सर्जरी की गई है। एम्स के प्लास्टिक, रिकंस्ट्रक्टिव और बर्न्स सर्जरी विभाग की ओर से सोमवार को जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार यह स्थिति सोमवार सुबह 11 बजे तक की है। इनमें 37 मामले पटाखों से जलने के हैं, जबकि दो लोग पोटाश से झुलसे हैं। पोटाश से झुलसने वालों में 13 साल का एक बच्चा भी शामिल है। फिलहाल 8 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है। झुलसने वालों में 10 वर्ष से कम उम्र के छह बच्चे हैं। इनमें सबसे कम उम्र का बच्चा पांच साल का है। आठ साल का एक बच्चा शरीर का 45 प्रतिशत हिस्सा जलने के कारण गंभीर स्थिति में है। 10 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 12 और 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 22 मामले हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र का एक मरीज भी शामिल है। एम्स ने बताया कि इसके अलावा आंखों में चोट के कुछ मरीज सीधे आरपी सेंटर के नेत्र आपातकालीन विभाग में आए हो सकते हैं। ऐसे मरीजों की संख्या इन आंकड़ों में शामिल नहीं की गई है।

हजरत निजामुद्दीन यार्ड में रेलवे पार्सल से 1,286 किलोग्राम संदिग्ध मांस जब्त, एफएसएल जांच के आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन यार्ड में रेलवे पार्सल के बीच लगभग 1,286 किलोग्राम ऐसा सामान मिला है, जिसके मांस होने का संदेह है। पुलिस ने एक अपुष्ट जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू की थी, जिसमें बताया गया था कि इस खेप में बीफ (गोमांस) हो सकता है, जिसे मटन या मांस बताकर ले जाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार, यह मामला 8 नवंबर 2026 को सामने आया, जब बड़ौदा हाउस स्थित रेलवे विजिलेंस यूनिट को सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली कि रेलवे यार्ड में आए एक कार्गो कंसाइनमेंट में संदिग्ध बीफ ले जाया जा रहा है। इस सूचना के बाद, जांच अधिकारी और स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) मौके पर पहुंचे ताकि माल की जांच की जा सके और जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके। पुलिस को थर्मोकोल के 20 कार्टन मिले, जिनमें ऐसा सामान था, जिसके मांस होने का संदेह है। इन पैकेजों का वजन लगभग 1,286.35 किलोग्राम था। यह माल हैदराबाद से ट्रेन नंबर 12721, 'दक्षिण एक्सप्रेस' के जरिए नई वाशिंग लाइन पहुंचा था। पुलिस द्वारा दी गई शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस माल को 'मटन' और 'मीट' बताकर बुक किया गया था। नमूने लेने और यह पता लगाने के लिए कि वह सामान असल में क्या है, मौके पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम और एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि इन नमूनों की जांच की जाएगी। साथ ही, 'ई-साक्ष्य' प्लेटफॉर्म के जरिए जरूरी कागजी कार्रवाई सहित अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। मौके पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीमें भी मौजूद थीं। पुलिस ने बताया कि नमूने लेने के बाद, जब्त किए गए सामान को नष्ट करने या उसके निपटान के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बात का पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि असल में वह सामान क्या था और उसे किस तरह से ले जाया जा रहा था। इससे पहले अक्टूबर में एक अलग मामले में, गुजरात के कलोल की एक सेशन कोर्ट ने तीन लोगों को गोहत्या और मांस बेचने की कोशिश करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अगस्त 2024 में पुलिस की एक छापेमारी के दौरान उनके पास से 277 किलोग्राम बीफ जब्त किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 55,000 रुपए थी। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

दिमागी नक्सल वाले बयान पर राहुल का पीएम को बहस की चुनौती, कहा...

पीएम ने हमें नक्सली कहा, मुझसे बहस करें

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को एक बार फिर खुली बहस की चुनौती दी है। इस बार उन्होंने सीधे सीआरपीएफ के जवानों को टैग करके पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि प्रिय सीआरपीएफ के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया - आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं। उन्होंने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती कायम है। वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, किसी भी जगह। मेरी गारंटी है उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। पिछले 8 दिन में यह छठी बार है, जब राहुल ने पीएम मोदी को बहस के लिए बोला है। दरअसल, पीएम मोदी ने इस बार दिवाली छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीआरपीएफ जवानों के साथ मनाई थी। राहुल ने उसी सेलिब्रेशन का एक वीडियो भी शेयर किया है। दरअसल, छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के बाद पीएम मोदी ने उन्हें संबोधित भी किया था। वहां पीएम ने कहा - ये पहली दिवाली है जब देश का हर जिला नक्सलवाद से मुक्त है। उन्होंने कहा- नक्सलवाद का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों का सफाया हो चुका है, लेकिन अब दिमागी नक्सलियों से खतरा है। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों ने कई राजनीतिक संगठनों में घुसपैठ कर ली है। हमें उनकी पहचान कर खत्म करना होगा। ये लोगों को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं।

मातृत्व-करियर संतुलन : एनसीडब्ल्यू का साझा जिम्मेदारी पर जोर

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि मातृत्व को महिलाओं के करियर में बाधा नहीं बननी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चे के जन्म के बाद भी महिलाएं अपनी पेशेवर यात्रा जारी रख सकें, इसके लिए माता-पिता के बीच बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का समान बंटवारा और मजबूत संस्थागत सहयोग जरूरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहाटकर के अनुसार, बच्चे की परवरिश माता और पिता दोनों की समान जिम्मेदारी है। उन्होंने एक इसतरह के सहयोगात्मक माहौल के निर्माण का आह्वान किया, जहां महिलाएं मातृत्व की जिम्मेदारियों को निभाकर अपनी पेशेवर आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश (लीव) के महत्व पर प्रकाश डाला, यह देखकर की मोदी सरकार यह सुविधा प्रदान कर रही है, लेकिन इस कोशिश को निचले स्तरों और निजी कंपनियों तक भी व्यापक रूप से पहुंचाने के प्रयासों की आवश्यकता है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को अपने सपनों को साकार करने और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, बिना मातृत्व से समझौता किए। उनका मानना है कि अगर माता-पिता मिलकर बच्चों का पालन-पोषण करें और आयोग द्वारा सुझाई गई अन्य सिफारिशों पर अमल हो, तब महिलाएं घर और बच्चों की देखभाल कुशलता से कर सकेंगी, साथ ही अपने करियर को भी जारी रख सकेंगी।

दिल्ली में सरकारी सेवाओं में देरी पर तय होगी जवाबदेही

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' (दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस एक्ट, 2026) को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों में सेवाओं के वितरण को निर्धारित समय-सीमा से बांधना और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। यह अधिनियम वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह एक अधिक आधुनिक और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि नए कानून से नागरिकों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा। सरकार अधिसूचना के माध्यम से यह तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी और प्रत्येक सेवा को उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम कितने दिन निर्धारित होंगे। प्रत्येक सेवा के लिए एक नामित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी कानून के दायरे में लाया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि इससे किसी आवेदन के लंबित रहने पर जिम्मेदारी तय करना आसान होगा। इस व्यवस्था का लाभ यह होगा कि नागरिकों को अपनी सेवा के लिए अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें यह जानकारी रहेगी कि उनका काम किस अधिकारी को करना है और उसे पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा क्या है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिनियम में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और उनकी निगरानी की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसके माध्यम से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। संबंधित विभागों को सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी।

उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्धारित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध कराना अथवा आवेदन अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में बताना संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। इससे नागरिकों को केवल अपने आवेदन की जानकारी लेने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही, विभागीय स्तर पर लंबित मामलों की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान स्वतः अपील (ऑटोमेटिक एस्कलेशन) की व्यवस्था है। यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो मूल आवेदन को ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जाएगा। नागरिक को केवल देरी के कारण अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। प्रत्येक विभाग में नामित अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह प्राधिकरण मामले की सुनवाई करेगा, आवश्यक होने पर सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देगा और देरी के लिए जिम्मेदारी भी तय कर सकेगा। उन्होंने बताया कि अपील का सामान्यतः 30 दिनों के भीतर निपटारा करना होगा। यदि प्राधिकरण निर्धारित अवधि में अपील का निपटारा नहीं करता है तो मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंचने की व्यवस्था भी की गई है। आयोग दूसरी अपीलों की सुनवाई करने के साथ कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। उसे सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने, विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करने, प्रक्रियाओं में सुधार सुझाने और आवश्यक मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने का अधिकार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए नियम में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। यदि बिना उचित कारण सेवा देने में देरी होती है तो संबंधित अधिकारी पर देरी के प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकेगा। इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा किसी आवेदन को अनुचित या बिना पर्याप्त कारण अस्वीकार करने पर 250 से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त अर्थदंड लगाया जा सकेगा। आर्थिक दंड लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त अवसर देना होगा। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनावश्यक देरी कम करना, शिकायतों का प्रभावी निपटारा करना और प्रशासन को नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को सम्मान, पारदर्शिता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका अधिकार सुनिश्चित करना है। समय पर सेवा मिलना नागरिक का अधिकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। नया समयबद्ध सेवा वितरण अधिनियम इसी सोच का परिणाम है।

एक्यूआई आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर दिल्लीवालों को धोखा दे रही सरकार : सौरभ भारद्वाज



नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में प्रदूषण के वास्तविक आंकड़ों के साथ भाजपा सरकार फर्जीवाड़ा कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब प्रदूषण को वास्तविक आंकड़ों से कम दिखाया जाएगा, तो इससे हार्ट अटैक, अस्थमा, रेस्पिरेटरी फेल्योर समेत अन्य गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार औसत एक्यूआई कम दिखाने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी का छिड़काव कर रही है और 20 स्टेशनों को हरे-भरे इलाकों में लगाया है। इस फर्जीवाड़े में शामिल होने के कारण ही शिकायत के बावजूद सीएक्यूएम और सीपीसीबी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि सरकार ने बाकायदा 20 नए मॉनिटरिंग स्टेशन हरे-भरे और खुले इलाकों में लगाए हैं। आनंद विहार और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में प्रदूषण, ट्रैफिक और आबादी ज्यादा है। इसलिए सरकार ने ऐसे नए इलाके ढूंढे जहां आबादी और ट्रैफिक कम है और हरे-भरे हैं। जब इसका औसत निकाला जाएगा, तो औसत कम हो जाएगा। इससे प्रदूषण कम नहीं होगा, मगर डेटा कम करके दिखाया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जहांगीरपुरी आईटीआई के एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर लगातार पानी छिड़का जा रहा है। प्रदूषण कम न हो, मगर पानी के छिड़काव से एक्यूआई का डेटा कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो सरकार दीवाली की रात को एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन बंद करा दे, उस सरकार पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार से हमारा निवेदन है कि जानता को सच्चा एक्यूआई दिखाइए। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो जो लोग बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, उनकी जान जा सकती है।

पेंशन वैलीडेशन एक्ट भेदभावपूर्ण, मोदी सरकार वापस ले: सुभाष लांबा

नई दिल्ली, एजेंसी।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने वित्त अधिनियम, 2025 के तहत लाए गए पेंशन वैलीडेशन प्रावधानों की तीखी आलोचना की है। उन्होंने इस एक्ट को पेंशनभोगियों के हितों पर सीधा हमला बताकर केंद्र सरकार से एक्ट को तत्काल वापस लेने की मांग की है। लांबा ने स्पष्ट किया कि यह नया कानून सरकार को सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशनभोगियों के बीच भेदभाव करने का अधिकार देता है, जिससे पुराने पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधन को लेकर गंभीर अनिश्चितता पैदा हो गई है।

उन्होंने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनभोगियों की पेंशन रिवीजन की स्पष्ट व्यवस्था न होने पर सवाल उठाए, विशेषकर तब जब इसमें गैर-अंशदायी पेंशन के खर्च को शामिल किया गया है। लांबा ने जोर देकर कहा कि पेंशन कर्मचारी की दशकों की सेवा से अर्जित सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, न कि सरकार की कृपा या वित्तीय बोझ। सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशनभोगियों को अलग-अलग वर्गों में बांटना सरासर अन्यायपूर्ण है और केंद्र सरकार को बंद करना चाहिए।

महासंघ के अध्यक्ष ने मांग की कि सरकार को 1 जनवरी, 2026 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों की पेंशन समान रूप रूप से संशोधित करने की स्पष्ट गारंटी देनी चाहिए। उन्होंने पीएफआरडीए एक्ट, एनपीएस और यूपीएस को कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को कमजोर करने वाला बताते हुए, इन तीनों को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को तत्काल बहाल करने की अपील की।

पेंशन वैलीडेशन एक्ट की वापसी, पुरानी पेंशन बहाली सहित कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर 12 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल कर्मचारी आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में कम्युटेशन राशि की वसूली 10 साल 8 महीने में करने, 65, 70 और 75 वर्ष की आयु में मूल पेंशन में 5 प्रतिशत की वृद्धि, आठवें वेतन आयोग में 3.8 फिटमेंट फैक्टर और 5 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 40 हजार रुपये वेतन, निजीकरण पर रोक, ठेका कर्मियों को नियमित करना, खाली पदों पर स्थायी भर्ती, टीईटी अनिवार्यता समाप्त करना और 18 महीने का डीए/ डीआर जारी करने की मांगें भी रखी जाएंगी। लांबा ने देशभर के कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों से इस रैली में भारी संख्या में शामिल होकर सरकार को अपनी एकजुट शक्ति का प्रदर्शन करने का आह्वान किया।

दीपावली पर सफदरजंग अस्पताल में 2 दिन में आए 135 बर्न इंजरी के केस, 129 पटाखों से जले

नई दिल्ली (एजेंसी)। दीपावली के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों से जलने के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के बर्न्स इमरजेंसी विभाग में 7 और 8 नवंबर को दो दिनों में दीपावली से जुड़े जलने के कुल 135 मामले दर्ज किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 129 मामले पटाखों से लगी चोट के कारण थे जबकि बाकी 6 मामले दीये से जलने के थे। दीपावली के मौके पर देशभर में कई जगहों से आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं। अधिकारियों के मुताबिक, दीपावली से जुड़ी चोटों के लिए इलाज कराने आए मरीजों में 35 बच्चे पटाखों से जलने के शिकार हुए और उनका अस्पताल की ओपीडी में इलाज किया गया। हालांकि, एक बच्चे को आगे के इलाज के लिए भर्ती करना पड़ा। त्योहार के दौरान बर्न इंजरी के मामलों में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए अस्पताल ने पहले से तैयारी कर रखी थी। अस्पताल ने दीपावली से जुड़े जलने के कारण भर्ती होने वाले मरीजों के लिए 20 बेड अलग से रखे थे। अधिकारियों ने बताया, 'इनमें से दीपावली से जुड़ी बर्न इंजरी से पीड़ित सात मरीज अभी अस्पताल में भर्ती हैं।' अस्पताल ने त्योहार के दौरान मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए जरूरी व्यवस्थाएं की थीं और प्रभावित लोगों को उचित चिकित्सा और इलाज देना जारी है। एहतियाती उपायों के महत्व को दोहराते हुए अस्पताल ने जोर दिया कि पटाखों से जुड़ी चोटों को रोकने और पूरे समुदाय की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता, जिम्मेदार तरीके से पटाखे जलाना और सावधानियों का सख्ती से पालन करना जरूरी है।

88 दिन से संसद का मानसून सत्र खत्म न होने पर अमित शाह पर कांग्रेस का आरोप, कहा...

परिसीमन बिल पास कराने दो-तिहाई बहुमत जुटाने की हो रही कोशिश

नई दिल्ली, एजेंसी।
कांग्रेस ने सोमवार को संसद के मानसून सत्र का औपचारिक समापन नहीं होने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर सत्रावसान नहीं किया। यानी औपचारिक तौर पर संसद सत्र का समापन नहीं किया। ताकि गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा में किसी तरह दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके। कांग्रेस का दावा है कि सरकार इस बहुमत के जरिए परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पास कराना चाहती है।

कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 88 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसका औपचारिक समापन यानी सत्रावसान नहीं किया गया है। उनके मुताबिक, यह अब तक का सबसे लंबा अंतर है।

2008 का रिकॉर्ड भी टूटा

मानसून सत्र की आखिरी बैठक 13 अगस्त को हुई थी। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, दोनों सदनों का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ। इससे पहले 2008 में मानसून सत्र के दौरान 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था। जयराम रमेश ने संसदीय कार्यप्रणाली पर लिखी किताब 'प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट' का हवाला देते हुए कहा कि आमतौर पर लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और उसके सत्रावसान के बीच दो से चार दिनों का अंतर होता है। इससे पहले अधिकतम अंतर 28 दिनों का रहा था, जो 2015 के मानसून सत्र में दर्ज किया गया था। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र में 2008 के मानसून सत्र का जिक्र करते हुए 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं होने की बात कही थी। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक भी अब नया रिकॉर्ड बन गया है।

